



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

अधिकार  
पत्रिका  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (4)  
PART II—Section 3—Sub-section (4)  
प्रकाशित की प्रमाणित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]  
No. 52]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2009/साथ 10, 1930  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2009/MAGHA 10, 1930

रक्षोपाय, सीमासुलभ एवं क्षेत्रीय दुष्प्रद शुल्क महसूलितालय  
अभिप्रेत

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2009

विषय : सीमायुक्त अल्पसंख्यक क्षेत्रों के आयकों के संबंधित रक्षोपाय जांच - प्राथमिक जांच महसूलिता

सं. 63(अ).— सीमासुलभ क्षेत्र अभिप्रेत, 1975 एवं उसके अन्तर्गत बनाव गए सीमासुलभ क्षेत्र (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) विधेय, 1997 को ध्यान में रखते हुए;

प्रक्रिया : भारत में सीमायुक्त अल्पसंख्यक क्षेत्रों के आयकों के संबंध में रक्षोपाय जांच की शुल्क से संबंधित सूचना दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को जारी की गई थी और उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी। सूचना की प्रति सभी उचित विचारक पक्षकारों को निम्नानुसार भिजवाई गई थी :—

## 2. चर्चा उत्पादक :

- (i) मै. तिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि., मुम्बई
- (ii) मै. ललितानन्द पेड्डे प्रोडक्ट्स लि.,
- (iii) मै. वेल्ड लिमिटेड लि., अहमदाबाद
- (iv) मै. इन्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली

## 3. आयतांक

- (i) फेन प्रा. लि., ए-67 एवं 68, मेरुप्रतापम, पीआईसीडीआईसी औद्योगिक क्षेत्र, पाण्डिचेरी-605009
- (ii) स्किन डाइकेम, ग्राम लैबनपारा, डाकघर-राधादासी-711309, झुझा, प. बंगाल
- (iii) साई सल्वेजेंट्स प्रा. लि., 21, प्रिंसिप स्ट्रीट, कोलकाता-700072, प. बंगाल

घ. रोहित सर्फेक्टेंट्स प्रा. लि. (धारी), केडीसी-चौबेपुर यूनिट, 117/एच-2/202, लखन नगर, कानपुर-200005, उत्तर प्रदेश

#### 4. निर्यातक

क) ईरान केमिकल इण्डस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कं. लेबिज नं. 91, सईदी स्ट्रीट, अफ्रीका एवेन्यू, तेहरान (19679), ईरान

ख) गल्फ फराबी पेट्रोकेमिकल कं., अल-जुबैल इण्डस्ट्रियल सिटी 1961, पी. ओ. बॉक्स 11763, सऊदी अरब साम्राज्य

ग) सीफ लिमिटेड, कतर, सीफ लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स : 50077, मेसाईद, स्टेट ऑफ कतर

घ) कोलमार ग्रुप एजी, लॉबेहॉफ, मेटलस्ट्रेस 9,6300 जुग, स्विट्जरलैंड

5. सूचना की प्रति निर्यातक देशों की सरकारों को नई दिल्ली स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से भिजवाई गई थी ।

6. इसी दिन सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों एवं आयातकों को प्रश्नावलियाँ भी भिजवाई गई थीं और उनसे 30 दिन के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

7. घरेलू उद्योग ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया ।

8. ज्ञात आयातकों- मै. फेन प्रा. लि., नई दिल्ली, साई सॉल्फोनेट्स प्रा. लि., 24 परगना और रोहित सर्फैक्टेंट्स प्रा. लि., कानुपर तथा निर्यातकों-गल्फ फराबी पेट्रोकेमिकल्स, सऊदी अरब साम्राज्य एवं सीफ लिमिटेड, कतर ने प्रारम्भिक आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं और विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय देने का अनुरोध किया ।

9. भारत के साबुन तथा डिटर्जेंट के बड़े स्तर तथा लघु स्तर के 24 विनिर्माताओं ने उन्हें हितबद्ध पक्षकार मानने का अनुरोध किया और विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय देने का अनुरोध किया । महानिदेशक ने इस पर विचार करने के बाद साबुन तथा डिटर्जेंट के 24 विनिर्माताओं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल करने की सहमति प्रदान की और समय सीमा की दिनांक 06.12.2009 तक बढ़ा दी गई । मूल सूचना के लिए भी समय सीमा बढ़ाकर 06.02.2009 कर दी गई । 24 नए “ हितबद्ध पक्षकारों ” के नाम, पते निम्नानुसार हैं :-

1	फैशन सूटिंग (प्रा.) लि. 3, छाबड़ा मेशन, पुरी रोड, भीलवाड़ा-311001
2	श्री यूनिकॉन ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. बीएस, एपीजी, 130 मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई-400023
3	ए आर सॉल्फोनेट्स प्रा. लि. प्लॉट नं. एन-41, एडिशनल अम्बरनाथ, एमआईडीसी आनंद नगर, जिला थाणे-421501, महाराष्ट्र
4	तमिलनाडु स्मॉल स्केल सोप एंड डिटर्जेंट्स चेतु “ डी ” अम्पा, चतुर्थ तल, नं. 37, पुराना नं. 110 नेल्सन मणिकेम रोड, चेन्नई-600029

5	शांति नाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लि. पी-15, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता- 700007
6	राजाराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 14, अजीज नगर, सेकेंड स्ट्रीट, कोडमबक्कम, चेन्नई-600024
7	किशोर सन्स डिटर्जेंट्स प्रा. लि. 15-9-469, महानूनगंज, हैदराबाद-500012 (आंध्र प्रदेश), भारत
8	हिन्दुस्तान युनिटीवर इकोनॉमिक लॉज प्रेक्टिस, एडवोकेट एंड सॉलिसीटर्स, 1502, डालामल टॉवर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
9	एडवांस सर्फैक्टेंट्स इंडिया लि. 511/2/1, रजोकड़ी, नई दिल्ली-110038
10	ए. आर. स्टेनकेम प्रा. लि., एक्सपोर्ट्स एंड मैनुफैक्चरर्स ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, सेकेंड फ्लोर, क्लेक एंड काल्वे बिल्डिंग कोलकाता-700001
11	न्यू इंडिया डिटर्जेंट्स लि. ए-2/25 मोडल टाउन-1, दिल्ली-110009
12	मै. स्मॉल स्केल्स डिटर्जेंट 43 यूरोपीयन एसियन लेन, कोलकाता- 700016
13	स्टैंडर्ड सर्फैक्टेंट्स लि. 8/5 आर्य नगर, कानपुर-208002
14	गोस मल हरि राम लि. 39, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015
15	डिटर्जेंट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, 148, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स-1, नई दिल्ली-110002
16	बड़कुर सर्फैक्टेंट्स प्रा. लि. यूनिटॉप हाउस, ईस्ट वेस्ट एस्टेट, सफेद पूल, अंधेरी कुर्ला रोड, मुम्बई-400072
17	इसरो प्रोडक्ट यूनिटॉप हाउस, ईस्ट वेस्ट एस्टेट, सफेद पूल, अंधेरी कुर्ला रोड, मुम्बई-400072
18	एस. कुमार्स डिटर्जेंट्स प्रा. लि. 4-डी स्थानीय विपणन केंद्र, ए ब्लॉक, रिंग रोड, नाशयणा नई दिल्ली-110028
19	साक्की-कैम 59 तथा 60, डीएसआईसीसी, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज-I नई दिल्ली-110020
20	हिपोलीन लि. मधुबन, चौथा तल, एलिस ब्रिज अहमदाबाद-380006
21	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिटर्जेंट मैनुफैक्चरर्स दिल्ली
22	महाराष्ट्र स्मॉल स्केल सॉप डिटर्जेंट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन मुंबई

23	गुजरात स्मॉल स्कैल डिस्ट्रिक्ट्स अहमदाबाद
24	पावर सोप्स लि. 62बी, नॉर्थ बोग रोड, टी नगर, चेन्नई-600017

10. आवेदन, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों एवं अपेक्षाओं द्वारा किए गए अतिरिक्त निवेदनों, जो गोपनीय से इतर हैं, को सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। घरेलू उद्योग, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचारों का सारांश निम्नानुसार है :

I. एलएबी के घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं :-

क) उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ विवरण शीर्ष 38170011 के अंतर्गत आने वाले “ सभी प्रकार रके लीनियर एल्काइल बेंजीन, मिक्स्ड अल्काइल बेंजीन ” के रूप में परिभाषित किया गया है। वाणिज्यिक भाषा में उपर्युक्त उत्पाद को सामान्यतः “ लीनियर एल्काइल बेंजीन ” (संक्षेप में एलएबी) कहा जाता है। सम्बद्ध वस्तुओं का प्रयोग लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फॉनिक एसिड अथवा लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फॉनिक एसिड के सोडियम लवण के विनिर्माण में किया जाता है। सभी लीनियर एल्काइल बेंजीन एवं सम्बद्ध वस्तुएं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 38.17 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

ख) जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 (12 माह) है। अनन्तिम शुल्क को तुरंत लागू किए जाने का मामला बनाने के लिए महानिदेशक कार्यालय के दिनांक 2 जनवरी, 2009 तथा 7 जनवरी, 2009 के पत्रों के संदर्भ में जांच अवधि के उपरांत की अवधि से संबंधित सूचना (जिस सीमा तक वह सुलभ है) भी उपलब्ध करा दी गई है।

ग) आयातों में न केवल निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है बल्कि उत्पादन तथा मांग के संदर्भ में भी वृद्धि हुई है।

घ) भारत में एलएबी के अधिकांश आयात कतर, ईरान और सऊदी अरब से किए जा रहे हैं। इन देशों और मध्य पूर्व के अन्य देशों में एलएबी की संयुक्त क्षमता का लगभग 70% निर्यात हेतु निर्धारित है। इन देशों की भौगोलिक निकटता और भारत में एलएबी के प्रयोगकर्ता क्षेत्र के कारण ये देश अपने निर्यात भारत की ओर करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। मिस्र में वर्ष 2007 में एक नए संयंत्र की शुरुआत से क्षमता में और वृद्धि होने की सम्भावना है। अतः यह देखा गया है कि उत्पादन क्षमता ने इस क्षेत्र के देशों पर एलएबी का भारी मात्रा में निर्यात करने पर दबाव डाला है (और वास्तव में 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान इन देशों से हुए निर्यातों में लगभग पाँच गुना वृद्धि हुई है और कैलेण्डर वर्ष 2007 के दौरान यह वृद्धि जारी रही है)। इन देशों में से अधिकांश में कुल उत्पादन में निर्यात के हिस्से के रूप में वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान भी वृद्धि हुई है।

ङ.) यह भी सूचित किया गया है कि यूएस तथा ईयू जैसे पारम्परिक बाजारों में एलएबी की खपत में स्थिरता आ गई है अथवा क्रमशः खपत में स्थिरता आ गई है अथवा क्रमशः गिरावट आई है। दूसरी ओर भारत, अत्यधिक वृद्धि के कारण एलएबी का एक बड़ा बाजार बन कर उभरा है। ये

कारक निर्यातक देशों के लिए कम कीमत पर एलएसी को भारी मात्रा में बेचने के लिए एक प्रोत्साहन सिद्ध हुए हैं।

घ) आयातों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 2% से 14% हो गया है। आयात विभिन्न देशों से और मुख्य रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र से कम कीमतों पर किए जा रहे हैं। क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि हुई है। तथापि घरेलू उद्योग की औसत निवल बिक्री प्राप्ति में हुई वृद्धि को लागत में हुई वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा सकता है। आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की प्रति मी. टन लागत में जांच अवधि के दौरान लगभग 33% की वृद्धि हुई है। तथापि यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत में इसी अवधि में केवल लगभग 23% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में हुई वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुक्रम नहीं है।

छ) घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में उपर्युक्त अवधि के दौरान लगभग 14% की निचयट आई। यह एक स्पष्ट संकेत है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में से एक प्रमुख हिस्से पर आयातों ने कब्जा कर लिया है।

ज) प्रमुख निर्यातक देशों से आयातों के औसत इकाई मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय फीकटोंफ कीमतों के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है; जैसा कि स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कीमतों में कमी किए बिना अपने विचार हिस्से को कायम नहीं रख पाए थे।

झ) घरेलू उद्योग की कीमतों में मंकी के बावजूद निर्यातक देशों द्वारा भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर की जा रही बिक्री के कारण आधार वर्ष अर्थात् 2004-05 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय निचयट आई है।

ञ) जांच अवधि के दौरान अधिकांश स्रोतों से हुए आयातों की घरेलू उद्योग के उत्पाद के रूप में बिक्री कम कीमत पर हुई है। याचिकाकर्ताओं के लिए इस समय प्रचलनस्थ/रुका अत्यन्त कठिन हो गया है और घरेलू उद्योग के लिए भी जीवित रह पाया उतना ही कठिन हो गया है। आक्रमक कीमत निर्धारण कार्यनीति के कारण सम्बद्ध आयातों ने उल्लेखनीय बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अतः निर्यातक देशों से इस समय आयातों में जो रही नाई वृद्धि पर रोक लगाने घरेलू उद्योग के हित में होगा।

ट) आयातों में हुई वृद्धि के बावजूद अलग-अलग क्षेत्रों में भारी निचयट और लगाई गई पूंजी से प्राप्त मामूली आय के कारण अनेक कंपनियों को लगातार क्षमता उपयोग की समस्या का सामना करना पड़ा है।

ठ) वर्ष 2004 से वित्तीय वर्ष 2007-08 के अंत तक उत्पादन क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, सेवगार, उत्पादकता, नफ़ा, नफ़ा प्रवाह, लगाई गई पूंजी से आय, आवद्ध प्रयोग, स्टॉक, खपत, बिक्री बाजार हिस्सा, कीमत एवं लागतका जैसे मानक्यों का व्यापक अध्ययन एलएसी के भारतीय उत्पादकों को हुई गम्भीर क्षति अथवा उल्लेखनीय अपक्षेय दर्शाता है। यह भी निश्चय किया गया है कि कम कीमतों पर किए गए आयातों में हुई वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई गम्भीर क्षति के बीच प्रत्यक्ष संबंध है; और आयातों में हुई वृद्धि का कीमतों पर बाव तब घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री की मात्रा में कमी के रूप में क्षतिपूर्ति प्रभाव पड़ा है।

ड) रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण को तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कम से कम 20%; तत्पश्चात् दूसरे वर्ष में 15% और तीसरे वर्ष में 10% रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का अनुरोध किया गया है। अपेक्षित स्तरों पर शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग अपने द्वारा किए गए अनेक उपायों अथवा तदनुसृत अवधि के दौरान प्रस्तावित उपायों के माध्यम से लागत को कम करने में समर्थ हो जाएगा। उद्योग को अपनी लाभप्रदता तथा आरओसीई में सुधार करने में समर्थ बनाने के लिए अन्तिम शुल्कों के माध्यम से उसका संरक्षण करने की आवश्यकता है।

ढ) घरेलू उद्योग के संघटकों ने अनेक निर्णय लेकर अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु उपाय किए हैं जिनमें (i) अवरोध हटाना; (ii) ऐसी अवरोध मुक्त क्षमताओं को फीडस्टॉक की आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि शामिल है। उपर्युक्त कदमों के कारण क्षमताओं में हुई वृद्धि से प्रचालन लागत अनुकूलतम बन जाने की सम्भावना है। चूंकि ये प्रचालन अवरोधों को हटाने से संबंधित है अतः इनसे स्थायी लागतों में मामूली वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग का प्रत्येक सदस्य पुनः रचना हेतु भिन्न दृष्टिकोण अपना रहा है। घरेलू उद्योग इस प्रयोजनार्थ तरल ईंधन के स्थान पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अनुमान है कि परिवर्तन की यह प्रक्रिया पूरी होने पर ऊर्जा की लागत में हुई बचत से एलएबी विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

II. हितबद्ध पक्षकारों के विचार : मै. हिन्दुस्तान यूनीलीवर कं. द्वारा दिनांक 16.10.2008 को किए गए अपने निवेदन में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :-

क) याचिकाकर्ताओं ने उस सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत नहीं किया है, जिसका दावा गोपनीय सचना के रूप में किया गया था। इससे एक सार्थक निवेदन करने के हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार पर गम्भीर आघात हुआ है।

ख) रक्षोपाय शुल्क जैसे व्यापार सुधार उपाय के प्रशासन में “जनहित” पर विचार करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस संबंध में यूनाइटेड फॉस्फोरस बनाम महानिदेशक रक्षोपाय, 2000 (118) ईएलटी 326 (दिल्ली) के मामले को उद्धृत किया गया है।

ग) एलएबी एक मध्यवर्ती उत्पाद है और यह डिटर्जेंट टिकिया और पाउडर के विनिर्माण की एक महत्वपूर्ण निविष्टि है और अंतिम उत्पाद की लागत में इसका योगदान लगभग 50% से 60% होता है। निविष्टि (एलएबी) की कीमतों में हुई किसी भी वृद्धि से आंशिक उत्पाद की लागत की निःसंदेह बढ़ जाएगी। भारत में डिटर्जेंट की माँग अत्यन्त लोचशील है और व्यवहार्य विकल्प के अभाव में उपभोक्ताओं को इसकी खरीद बढ़ी हुई कीमतों पर करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

घ) एलएबी की कीमत बढ़ गई है और कीमतों में हुई वृद्धि की परिणति डिटर्जेंटों की कीमतों में हुई आनुपातिक वृद्धि के रूप में हुई है और इसने लगभग 20 करोड़ भारतीय परिवारों को प्रभावित किया है क्योंकि डिटर्जेंट टिकिया और पाउडर का उपयोग प्रत्येक भारतीय परिवार में किया जाता है। इसके अलावा भारत के डिटर्जेंट उद्योग में हजारों छोटी-छोटी यूनितें, लघु उद्योग और कुछेक मध्यम एवं बड़े विनिर्माता शामिल हैं। एलएबी उद्योग की तुलना में डिटर्जेंट उद्योग अत्यधिक श्रम गहन है। इनमें पाँच लाख से अधिक कामगार नियोजित हैं, जो केवल लगभग 500 कामगारों को रोजगार देने वाले एलएबी उद्योग की तुलना में काफी अधिक है। भारत में एलएबी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर दिए जाने की स्थिति में निचले स्तर के डिटर्जेंट उद्योगों की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और इस प्रकार इस उद्योग में नियोजित लाखों कामगारों की आजीविका प्रभावित होगी।

(अ) घरेलू उद्योग के चारों संघटक बहु-उत्पाद, वृहत् विनिर्माण कंपनियां हैं। एलएबी का विनिर्माण एवं उत्पादन इन कंपनियों के समग्र व्यवसाय का एक छोटा हिस्सा मात्र है। याचिकाकर्ताओं के वृहत्ताकार और उनके उत्पाद पोर्टफोलियो में एलएबी की अपेक्षाकृत छोटी उपस्थिति को देखते हुए इस बात की संभावना नहीं है कि उन्हें केवल एलएबी के आयातों के कारण "अत्यधिक समग्र क्षति" का सामना करना पड़े।

(ब) घरेलू उद्योग द्वारा एलएबी के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु कुल घरेलू खपत में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट के समानान्तर घरेलू उद्योग के निर्यात उत्पादन में सदृश वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि घरेलू उद्योग की बिक्री के पैटर्न में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है जो निर्यातों की तरफ अधिक है। कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में निर्यातों का हिस्सा बहुत अधिक है जो यह दर्शाता है कि भारत में उत्पादित एलएबी को उत्तरोत्तर निर्यात बाजार में भेजा जा रहा है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, यदि कोई हो, स्वयं के कारण है और उससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति प्रदर्शित नहीं होती है।

(छ) याचिकाकर्ता क्षमता उपयोग के अत्यधिक उच्च स्तरों पर प्रचालन कर रहे हैं।

(ज) आयातों से संबंधित अद्यतन आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की उपस्थिति या उसके खतरे का निर्धारण करना माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सतत प्रयास है।

(झ) याचिकाकर्ता एलएबी के बड़े हुए आयातों और उन्हें हो रही कथित गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की उपस्थिति स्थापित करने में असफल रहे हैं।

(ञ) याचिकाकर्ता द्वारा उनके संयंत्रों के बंद होने के दावे भ्रामक हैं। तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. दोनों बड़े पेट्रो-रसायन विनिर्माता हैं और संयंत्रों के बंद होने संबंधी सूचना संभवतः सामान्य अनुरक्षण तथा उन्नयन प्रयोजनों एवं फीडस्टॉक की अनुपलब्धता के कारण अस्थायी रूप से बंद होने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावों के विपरीत उनके संयंत्र भारत से एलएबी के आयातों में वृद्धि तथा एलएबी की बिक्री में उनकी असमर्थता के कारण बंद नहीं थे बल्कि सामान्य टूटफूट की मरम्मत जैसे अस्थायी कारणों से बंद थे। वस्तुतः याचिकाकर्ताओं ने एलएबी का उत्पादन और घरेलू एवं निर्यात बाजार में उसकी बिक्री जारी रखी।

(ट) एलएबी के उपभोक्ताओं को घरेलू स्रोतों से एलएबी की खरीद में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे एलएबी के प्रयोक्ता वैकल्पिक व्यवस्था करने और आयातों के जरिए अपनी मांग को पूरा करने के विकल्प का पता लगाने पर विवश हुए हैं। घरेलू उत्पादकों में घरेलू बिक्री को निर्यातों से प्रतिस्थापित करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से घरेलू रूप से एलएबी की खरीद में कठिनाई और भी बढ़ गई है।



(ब) अपनी याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विवरणों की समीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि बड़े हुए आयातों को समायोजित करने के उनके प्रयास पूर्णतः अपर्याप्त हैं और उनके इन दावों कि बड़े हुए आयातों से उन्हें क्षति हो रही है, की असंगति को दर्शाते हैं।

(ड) उपर्युक्त के आलोक में भारत में एलएबी के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा मौजूद नहीं है।

III. मै. फेना (प्रा.) लि., नई दिल्ली, एड्वान्स सर्फेक्टेंट्स इंडिया लि., नई दिल्ली, ए.आर. स्टेन्कम, कोलकाता, न्यू इंडिया डिटरलजेंट्स लि., नई दिल्ली, रोहित सर्फेक्टेंट्स (प्रा.) लि., कोलकाता, लघु डिटरजेंट्स एवं साबुन विनिर्माता एसोसिएशन, कोलकाता और स्टैण्डर्ड सर्फेक्टेंट्स लि., कानपुर ने दिनांक 14.1.2009 को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए महानिदेशक, रक्षोपाय के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख तर्क निम्नानुसार हैं:-

(क) आयात संबंधी आंकड़े पुराने हैं और वे मामले की वर्तमान स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। जांच दिसंबर 2008 में शुरू की गई थी। तथापि, याचिकाकर्ता ने केवल वित्त वर्ष 2007-2008 तक के आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जब जांच शुरू की जाती है तब जांच शुरुआत की तारीख से निकटतम तारीख तक के आयात आंकड़े दिए जाने चाहिए। घरेलू उत्पादकों से चालू वर्ष 2008-09 की पूरी हो चुकी तीन तिमाहियों के लिए अपनी उत्पादन लागत, बिक्री राजस्व आदि के साथ-साथ आयातों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करते हुए संशोधित और अद्यतन याचिका प्रस्तुत करने को कहा जाए।

(ख) घरेलू उत्पादकों के संयंत्र चालू हैं और इसलिए संयंत्रों के बंद होने संबंधों का दावा गलत है।

(ग) उत्पादन में गिरावट नहीं आई है।

(घ) एलएबी का विनिर्माण करने वाले बड़े औद्योगिक समूहों की तुलना में एलएबी के अंतिम प्रयोक्ता मझोले एवं लघु उद्यम हैं। एलएबी उत्पादक उत्पादक संघ के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपनी कीमतें कृत्रिम रूप से उच्च स्तरों पर बनाए रखी हैं। चारों घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रभारित घरेलू बिक्री कीमतें हमेशा एकसमान रही हैं। घरेलू बिक्री कीमतें उस कीमत से बहुत अधिक हैं जिस पर वे अन्य देशों को निर्यात करते हैं, आयात कीमतों का स्तर उनकी घरेलू कीमतों और निर्यात कीमतों के बीच में है।

(ङ) एलएबी के भारतीय अंतिम प्रयोक्ताओं को एलएबी के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रभारित उच्च कीमतों का भुगतान करना पड़ रहा है और रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए वर्तमान याचिका केवल अतिरंजित लाभों को बनाए रखने के लिए है।



(च) एलएबी पर पहले से ही 7.5% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है। प्रसंस्कृत उपभोक्ता डिटर्जेंट उत्पादों पर 10% का उच्चतम आयात शुल्क लगता है। अतः एलएबी पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से एक प्रतिकूल शुल्क संरचना उत्पन्न हो जाएगी जहां बुनियादी कच्चे माल पर सीमा शुल्क प्रसंस्कृत उत्पादों पर लागू शुल्क से अधिक होगा।

(छ) एलएबी की लगत में किसी वृद्धि में डिटर्जेंट्स की कीमतें प्रभावित होंगी और अंततः इसका परिणाम डिटर्जेंट्स के कम उत्पादन और बिक्री के रूप में होगा। एलएबी के 4 विनिर्माताओं की तुलना में भारत ने डिटर्जेंट्स के 4,000 से अधिक विनिर्माता हैं। एलएबी उत्पादकों द्वारा नियोजित 500 व्यक्तियों की तुलना में ये विनिर्माता 500,000 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं। इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क लगाने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।

(ज) मौजूदा मामले में ऐसी "निर्णायक परिस्थितियां" मौजूद नहीं हैं जिनके लिए अनन्तिम रक्षोपाय का अधिरोपण वांछित हों।

(झ) इस बात का भी विरोध किया गया है कि गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए धारा

4.2 (क) के अंतर्गत "सभी संगत कारकों" पर विचार करना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

(ञ) इसके अतिरिक्त एलएबी की निर्यात कीमतें प्रायः भारतीय एलएबी विनिर्माताओं की निर्यात कीमत से अधिक हैं। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा कुल घरेलू उत्पादन के कम से कम 30% का निर्यात किया जा रहा है। यह मानना अवास्तविक होगा कि यदि घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में हानि हो रही हो तो वे कम कीमतों पर इतनी अधिक मात्रा में निर्यात करेंगे।

(ट) आयातकों के पास उपलब्ध बाजार आसूचना के अनुसार घरेलू उद्योग की औसत निबल बिक्री आय और मार्जिन 5% से 23% के बीच है।

(ठ) निर्णायक परिस्थितियों का कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ड) उन्होंने यह भी विरोध किया है कि अनन्तिम या अंतिम उपायों का अधिरोपण "सार्वजनिक हित" के विरुद्ध होगा और एओएस के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों (आयातक, निर्यातक, उत्पादक आदि) द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई करना या उन्हें अन्य उपयुक्त तरीके उपलब्ध कराना जांचकर्ता प्राधिकारी का दायित्व है।

(ढ) इसके अतिरिक्त दिनांक 19 दिसम्बर 2008 की जांच शुरुआत अधिसूचना में ऐसी अपरिक्लिप्त परिस्थितियों का कोई संदर्भ नहीं है जो डब्ल्यूटीओ के समक्ष भारत द्वारा ली गयी वचनबद्धताओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी।

(ण) मध्य पूर्व के चार निर्यातक देशों में कुल क्षमता केवल 15000 टन या मात्र 4.6% है और इसलिए उससे घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति का खतरा उत्पन्न नहीं होता है, इसके अभाव में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसे गौण क्षमता संयोजन व्यवसाय में आम हैं और अधिक से अधिक उपयुक्त परिवर्तनों को "परिस्थितियां" कहा जा सकता है परंतु उन्हें कभी भी "भारत द्वारा लिये गये दायित्वों के परिणामस्वरूप अपरिक्लित परिस्थितियां" नहीं कहा जा सकता।

(त) जैसा कि ऊपर कहा गया "और घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया" कच्चे माल में अपेक्षाकृत फायदा कीमतों और मात्राओं में प्रदर्शित होता है जिसके लिए कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। मध्य पूर्व में तेल का उत्पादन कई दशकों से सर्वज्ञात कारक है। रक्षोपायों सहित व्यापार उपचार उपायों का उद्देश्य कंपनियों को अपनी राष्ट्रीय सरकारों से सुरक्षा की मांग करके "सामान्य से अधिक लाभ" प्राप्त करने की अनुमति देना नहीं है।

(थ) इस बात का विरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा कोई विश्वसनीय पुनर्गठन योजना प्रस्तुत नहीं की गयी है।

IV. मैं. फेना (प्रा.) लि, नई दिल्ली, एडवांस सर्फैक्टेंट्स इंडिया लि., नई दिल्ली, ए.आर. स्टानकैम प्रा. लि., कोलकाता, न्यू इंडिया डिटर्जेंट्स लि., नई दिल्ली, रोहित सर्फैक्टेंट्स (प्रा.) लि. कानपुर, साई सल्फोनेट्स प्रा.लि., कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लि. कोलकाता, स्मॉल स्केल डिटर्जेंट्स एंड सोप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, कोलकाता तथा स्टैंडर्ड सर्फैक्टेंट्स लि., कानपुर के प्रतिनिधियों ने दिनांक 23.1.09 को अनिवार्य अभ्यावेदन दर्ज किया। प्रमुख अभ्यावेदन निम्नानुसार है:

(क) यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में ऐसी "संकटकालीन स्थितियां" मौजूद नहीं हैं जिनके कारण अनंतिम रक्षोपाय लागू करने की आवश्यकता हो। अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने डब्ल्यूटीओ में अर्जेंटीन-फुटवियर मामले, जनवरी 2000 में आयोजित टेक्सटाइल निगरानी निकाय (टीएमवी) की बैठक, और संकटकालीन स्थितियों की मौजूदगी की आवश्यकता दर्शाने हेतु रक्षोपाय संबंधी करार का संदर्भ लिया है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया है कि गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए अनुच्छेद 4.2(क) के अंतर्गत सभी संगत कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने अपीलीय निकाय में यूएस-व्हीट ग्लुटेन मामले और कोरिया-डेयरी मामले पर पैनल रिपोर्ट का संदर्भ दिया है।

(ख) अनंतिम शुल्क लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली गंभीर क्षति अथवा संकटकालीन स्थितियों के अभाव संबंधी अपने तर्क के संबंध में उन्होंने कहा है कि संकटकालीन स्थितियों का निर्धारण करने के लिए पुराने आंकड़े संगत नहीं हैं। यह तथ्य निर्विवाद है कि एलएबी की उत्पादन लागत पूर्ण रूप से कच्चे माल की कीमतों पर आधारित है लेकिन घरेलू कीमतों से कच्चे माल की कम होती कीमतें प्रदर्शित नहीं होती हैं।

(ग) इसके अलावा एलएबी की आयात कीमतें अधिकांशतः भारतीय एलएबी विनिर्माताओं की निर्यात कीमत से अधिक हैं। यह देखा जा सकता है कि कुल घरेलू उत्पादन का कम से कम 30% घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किया जा रहा है। यह अनुमान लगाना अवास्तविक होगा कि यदि घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में हानि हो रही होती तो वे ऐसी उच्च मात्रा में निर्यात कमतर कीमतों पर करते।

(घ) आयातकों के पास उपलब्ध बाजार आसूचना के अनुसार औसत निवल बिक्री आय तथा घरेलू उद्योग के मार्जिन में -5% से 5% का अंतर है।

(ङ) घरेलू उद्योग यह स्वीकार करता है कि संभवतः रोजगार से घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का संकेत न मिले। दूसरी ओर अनंतिम उपायों को लागू करने से डिटर्जेंट उद्योग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा जिसमें हजारों लघु इकाइयां, के वी आई सी इकाइयां, लघु स्तरीय उद्योग तथा कुछेक मध्यम और बड़े स्तर के विनिर्माता शामिल हैं। यह पांच लाख से अधिक कामगारों को रोजगार देता है और भारत के 200 मिलियन घरों में रहने वाले 120 करोड़ से अधिक लोगों के कपड़े धोने की स्वच्छता संबंधी दैनिक जरूरतों को पूरा करता है।

(च) उन्होंने यह तर्क भी दिया है कि अनंतिम अथवा अंतिम उपायों को लागू करना "लोक हित" के विरुद्ध होगा और एओएस के अनुच्छेद 3.1 में जांच प्राधिकारियों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे जांचाधीन मामले के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने और अन्य पक्षों के विचारों पर प्रतिक्रिया देने का समुचित अवसर प्रदान करने के लिए हितबद्ध पक्षों (आयातक, निर्यातक, उत्पादक आदि) के लिए सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करें। एक ऐसा मुद्दा जिस पर विभिन्न पक्षों के विचार जानने की आवश्यकता है, यह है कि रक्षोपाय लोक हित में हैं अथवा नहीं।

(छ) वर्तमान मामले में डिटर्जेंट उद्योग में हजारों छोटी इकाइयां, के वी आई सी इकाइयां, लघु उद्योग और कुछ मझोले एवं बड़े विनिर्माता शामिल हैं जो पांच लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं जबकि LAB उद्योग में केवल चार बड़ी औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं तथा उनसे केवल 500 श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त, डिटर्जेंट उत्पादों के कच्चे माल की लागत में 50-60% हिस्सा LAB का ही बनता है। कुछ LAB का उपयोग निर्धन कृषकों द्वारा कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों तथा इमल्सिफायर्स जैसे अन्य उत्पादों और वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त वस्त्र सहायक सामग्री जैसे अन्य रसायनों के विनिर्माण के लिए किया जाता है। दूसरी ओर LAB के चार घरेलू विनिर्माताओं में से दो फॉर्थून 500 कंपनियां हैं जिनके लिए LAB व्यवसाय गौण है अर्थात् उनके कुल व्यवसाय के 1% से भी कम है। अतः यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में अनंतिम/अंतिम रक्षोपाय लागू करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध और एओएस के अनुच्छेद 3.1 का उल्लंघन होगा।

(ज) घरेलू उद्योग इस बात का विरोध करता है कि जांच की शुरुआत गैट 1994 के अनुच्छेद XIX के उल्लंघन में है क्योंकि कोई असंभावित अपरिकल्पित घटना नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त, गैट 1994 के अनुच्छेद XIX के अनुसार कोई रक्षोपाय तभी लागू किया जा सकता है, जब अपरिक्लित घटनाओं के कारण आयातों में अकस्मात वृद्धि हो और यह वृद्धि गैट के अंतर्गत किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा लिए गए दायित्वों के परिणामस्वरूप हो जिससे उस संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो अथवा गंभीर क्षति का खतरा हो ।

(झ) मध्य पूर्व के चार देशों अर्थात् ईरान, इराक, सउदी अरब तथा यूएई में क्षमता संयोजन केवल 15,000 टन या 4.6% है ।

(ञ) इसके अतिरिक्त, याचिका में ही यह स्वीकार किया गया है कि मध्य-पूर्व के विपरीत भारतीय विनिर्माताओं पर उच्च ऊर्जा एवं विद्युत लागतों का भार है । यह नोट किया जाए कि कच्चे माल की बहुतायत में उपलब्धता के कारण वैश्विक व्यापार में मध्य-पूर्व को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है । इसके अलावा, यह तुलनात्मक लाभ आने वाले वर्षों में भी उपलब्ध रहेगा और उरुगे दौर की वार्ताओं के समय भी यह अनुमेय था । तुलनात्मक लाभ के विरुद्ध रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण का तात्पर्य किसी निर्यातक के पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए उसे दंडित करना होगा जो आम तौर पर डब्ल्यू टी ओ करार तथा विशेष रूप से AOS के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध होगा ।

(ट) यह विरोध किया गया है कि याचिका में उल्लिखित मापदंड "गंभीर क्षति" या "गंभीर क्षति के खतरे" का समर्थन नहीं करते हैं, यथा:-

- जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग 95% के स्तर तक पहुंच गया था ।
- पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वस्तु सूची में गिरावट आई है ।
- वर्ष 2007-08 के दौरान उत्पादन मात्राओं में कोई गिरावट नहीं आई है । इसके विपरीत वर्ष 2006-07 में उत्पादन 4.65 लाख मी. टन से बढ़ कर वर्ष 2007-08 के दौरान 4.71 लाख मी. टन हो गया है ।
- यह विरोध किया गया है कि याचिका में उल्लिखित मापदंड "गंभीर क्षति" या "गंभीर क्षति के खतरे" का समर्थन नहीं करते हैं ।

(ठ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया कच्चे माल में तुलनात्मक लाभ कीमतों और मात्राओं में प्रदर्शित होता है जिसके लिए कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता है । मध्य पूर्व में तेल का उत्पादन कई दशकों से व्यापक रूप से ज्ञात कारक है । रक्षोपाय सहित व्यापार उपचार उपायों का उद्देश्य संरचनात्मक समायोजना को सुकर बनाना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बाधित होने के बजाय उससे सुधार होगा । यह विरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा कोई विश्वसनीय पुनर्संरचना योजना प्रस्तुत नहीं की है । अतः उपाय तब तक लागू नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि वे गंभीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित न हों और समायोजना को सुकर बनाते हों ।

(ड) इसके अतिरिक्त, लागत में प्रस्तावित कमी और लागू शुल्कों के स्तर या अपेक्षित शुल्कों के स्तर में कोई सह-संबंध प्रदर्शित नहीं होता है।

V. घरेलू उद्योग द्वारा आगे के अभ्यावेदन : आवेदकों ने दिनांक 22 जनवरी 2009 को अतिरिक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं-

(क) मै. हिंदुस्तान यूनिलीवर लि. के उत्तर में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया कि उन्होंने प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय रूपान्तर में गंभीर क्षति के संबंध में समस्त अगोपनीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यह निवेदन किया गया है कि उन्होंने विभिन्न क्षति कारकों के संबंध में सभी सूचिबद्ध आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवेश पर आय आदि जैसे विभिन्न स्वतंत्र क्षति कारकों की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। लागत, लाभप्रदता, आरओआई आदि से संबंधित आंकड़े अत्यधिक व्यवसाय संवेदनशील सूचना है जिसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होगा और उनका व्यवसाय प्रतिकूलतः प्रभावित होगा। अतः घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमों के नियम 7(1) के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है और सूचिबद्ध आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

(ख) रिलायंस के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में यह मामला बिल्कुल भी संगत नहीं है और उसका उल्लेख किसी संदर्भ के बिना किया गया है। उस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गोपनीयता का दावा किया था और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के उपबंधों के अनुसार गोपनीयता का दावा करने का अधिकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास नहीं था। अतः उक्त निर्णय संगत नहीं है।

(ग) घरेलू उद्योग की विस्तृत पुनर्संरचना योजनाएं आवेदन के गोपनीय रूपान्तर के साथ संलग्न की गयी हैं। चूंकि ये योजनाएं कंपनी विशिष्ट हैं और उनमें वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना शामिल है, अतः घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली के नियम 7(1) के अंतर्गत सुरक्षा की मांग की थी, अतः पुनर्संरचना योजनाओं के ब्यौरे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ बांटे नहीं जा सकते हैं।

(घ) जहां तक सार्वजनिक हित का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि एचयूएल के तर्क में कोई पात्रता नहीं है क्योंकि रक्षोपाय विधान बड़े हुए निर्यातों से देश के घरेलू उद्योग के वैध हितों की रक्षा करने के लिए है। यदि एचयूएल के सर्क को स्वीकार किया जाता है, तो इससे समग्र रक्षोपाय विधान निरर्थक हो जाएंगे क्योंकि रक्षोपाय शुल्कों के जरिए प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य बड़े हुए निर्यातों से घरेलू उद्योग की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से एकाधिकार की प्रथा को प्रोत्साहन नहीं मिलता है बल्कि यदि बड़े हुए आयातों से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो या उसका खतरा हो तो घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा होती है ताकि उन्हें बड़े हुए निर्यातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

(ड.) 'सार्वजनिक हित' शब्द का दायरा केवल उपभोक्ता हित को शामिल करने तक सीमित नहीं है। 'सार्वजनिक हित' एक व्यापक शब्द है जिसके दायरे में विनिर्माताओं के हित सहित व्यापक सामुदायिक हित का सामान्य समाज कल्याण भी शामिल है। यद्यपि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का परिणाम भारत में आयातित एलएबी की बढ़ी हुई लागत के रूप में होगा, तथापि रक्षोपाय विधानों के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इसके अधिरोपण का उद्देश्य बढ़े हुए आयातों की स्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने हेतु घरेलू उद्योग को पर्याप्त समय प्रदान करना है। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से प्रयोक्ताओं/ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत पर अपनी सामग्री संबंधी अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

(च) एचयूएल ने सार्वजनिक हित हेतु अपने तर्कों के समर्थन में यूनाइटेड फास्फोरस बनाम महानिदेशक (रक्षोपाय) के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का सहारा लिया है। हमारे इस विरोध कि रक्षोपाय विधानों के संदर्भ में सार्वजनिक हित पूरा होगा यदि घरेलू विनिर्माताओं को बढ़े हुए आयातों से सुरक्षा प्रदान की जाए, के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना यह निवेदन किया जाता है कि उक्त निर्णय का उल्लेख संदर्भ के बिना किया गया है। उस मामले में महानिदेशक ने निर्णय लिया था कि चूंकि घरेलू उद्योग ने उत्पादन बंद कर दिया था, यह आकलन करना कठिन होगा कि तीन वर्षों के बाद भी घरेलू प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर देशी उत्पादन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अतः महानिदेशक ने पुनर्संरचना योजना की सफलता की संभावना जैसे संगत कारकों पर विचार करने के बाद रक्षोपाय शुल्कों की सिफारिश न करने का निर्णय लिया था। अतः यह प्रत्यक्ष है कि महानिदेशक का निर्णय कुछ समय में घरेलू उद्योग के बेहतर निष्पादन करने में अक्षमता पर आधारित था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय केवल इसी संदर्भ में था जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि महानिदेशक को नियमों के अंतर्गत अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा। ऐसी कोई अफवाह भी नहीं है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से महानिदेशक को सार्वजनिक हित के पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार करने का अधिकार हुआ है कि ताकि प्रयोक्ता उद्योग के हितों को भी शामिल किया जा सके। अतः यह दोहराया जाता है कि रक्षोपाय नियमों में की गई परिकल्पना तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक हित तभी पूरा होगा यदि विचाराधीन उत्पादन के घरेलू उत्पादकों की स्थिति की जांच नियमों के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों के आधार पर की जाए।

(छ) एचयूएल तथा आयातकों/अंतिम प्रयोक्ताओं से इस संबंध में विस्तृत सूचना देने को कहा जा सकता है कि अपरिष्कृत माल की कीमतों में समग्र वृद्धि के कारण जब एलएबी की कीमतें बढ़ गई थीं तब डिटर्जेंट उद्योग में रोजगार की स्थिति किस प्रकार प्रभावित हुई थी। यह स्पष्ट हो जाएगा कि एचयूएल और आयातक पहले से घाटे में चल रहे एलएबी उद्योग की

कीमत पर अपने लाभ मार्जिनों की सुरक्षा के लिए रोजगार एवं वृहत सार्वजनिक हित का मुद्दा उछाल रहे हैं ।

(ज) घरेलू उद्योग भी देश में कई व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान मिलता है । रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से केवल घरेलू उत्पादकों को बड़े हुए आयातों के जरिए प्रतिस्पर्धा के नए रूप का सामना करने के लिए समय मिलेगा जिससे दीर्घावधि में एलएबी के ग्राहकों और अंतिम प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं को लाभ होगा ।

(झ) एचयूएल ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं हुई है । यह तर्क भी आधारहीन है क्योंकि घरेलू उद्योग ने एलएबी के बड़े हुए आयातों से हुई गंभीर क्षति के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं ।

(ञ) गंभीर क्षति : एचयूएल ने दावा किया है कि एलएबी के बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है । इस संदर्भ में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) के खंड 6(ग) के उपबंधों का उद्धरण देना संगत होगा जिसमें 'गंभीर क्षति' को एक ऐसी क्षति जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति में अत्यधिक समग्र बाधा पहुंचे के रूप में परिभाषित किया गया है, इसके अतिरिक्त यह निर्धारित करते समय कि बड़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है या पहुंचने का खतरा है, रक्षोपाय नियमों के अनुबंध में महानिदेशक द्वारा उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले वस्तुपक्ष एवं निर्धारण-योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों, विशेष रूप से सापेक्ष एवं तुलनात्मक रूपों में संबंधित वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर एवं मात्रा, बड़े हुए आयातों द्वारा प्राप्त किया गया घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन का आकलन किया जाना अपेक्षित है ।

(ट) विभिन्न मापदंडों के विश्लेषण से यह स्पष्टतः प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को बड़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति हुई है । आयातों में सापेक्ष रूप से और देश में प्रत्यक्ष खर्च की तुलना में वृद्धि हुई है जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार हिस्से का एक बड़ा हिस्सा सस्ते आयातों ने ले लिया है ।

(ठ) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि सभी प्रमुख आर्थिक एवं वित्तीय मापदंडों पर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है । घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है । बड़े हुए आयातों के दबाव के साथ-साथ पूर्ववर्ती लाभ से अब घाटे की स्थिति और लगाई गई पूंजी पर मामूली आय के कारण अधिकांश कंपनियों को कम क्षमता उपयोग का सामना करना पड़ा । कीमतों पर दबाव और घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई मात्रा में कमी में रूप में बड़े हुए आयातों का क्षतिकारक प्रभाव रहा है ।



(ड.) घरेलू उद्योग द्वारा उच्च क्षमता उपयोग के संबंध में यह निवेदन किया गया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट देखी गई है। यदि बढ़े हुए आयात न होते तो घरेलू उद्योग प्राप्त करने योग्य क्षमता की दृष्टि से किसी कठिनाई के बिना अतिरिक्त मांग को पूरा कर पाया होता।

(ढ) एचयूएल ने कहा है कि चूंकि एलएबी याचिकाकर्ता के समग्र व्यवसाय का एक बहुत छोटा प्रतिशत बनता है, अतः यह असंभावित है कि उन्हें केवल एलएबी के आयातों में वृद्धि के कारण अत्यधिक समग्र क्षति का सामना करना पड़े, यह उल्लिखित है कि रक्षोपाय शुल्क उत्पाद विशिष्ट होता है। बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधित उत्पाद अर्थात् एलएबी के कारण है न कि अन्य उत्पादों के कारण। अधिकांश याचिकाकर्ता कंपनियां बहु-उत्पाद कंपनियां हैं। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जब उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकों, बिक्री एवं लाभ के आधार पर ऐसा अलग अभिज्ञान संभव हो, तब क्षति वशिलेण विषयगत विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाता है न कि समग्र कंपनी के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी {2006(202)ईएलटी 23 (एस सी)} के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस स्थिति की पुष्टि की गई है। यही अनुपात रक्षोपाय शुल्कों पर भी लागू होगा। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अभ्यावेदनों से यह स्पष्ट है कि एलएबी के बढ़े हुए आयातों के कारण उन्हें लैब में गंभीर क्षति हुई है और उनके अन्य प्रचालनों के संदर्भ का वैधानिक एवं तार्किक रूप से कोई महत्व नहीं है।

(ण) एचयूएल ने दावा किया है घरेलू बिक्रियों को निर्यातों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में यह निवेदन है कि आरओआई में अत्यधिक कमी और सस्ते एवं बढ़े हुए आयातों के कारण घटी हुई घरेलू कीमतों के बावजूद अत्यधिक कीमत कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री के साथ-साथ हानि की स्थिति से घरेलू उद्योग निर्यात बाजारों में अपना हिस्सा बढ़ाने पर विवश हुआ है। यदि घरेलू उद्योग निर्यात न करने का निर्णय लेता है तो इससे उसके कुल उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप समग्र लागतों एवं घाटों में वृद्धि होगी। वस्तुतः यदि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपनी बिक्रियों में वृद्धि कर पाता है तो वह जरूर ऐसा करना चाहेगा ताकि घरेलू बाजार में बेहतर आय हो। वस्तुतः इस आवेदन का समग्र उद्देश्य घरेलू बाजार में बाजार हिस्से में वृद्धि करना है। अतः, एचयूएल के तर्क में कोई अर्हता नहीं है।

(त) इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बढ़े हुए आयात नहीं हैं क्योंकि घरेलू मांग एवं घरेलू आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए ये आयात आवश्यक थे, यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग के लिए निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में बिक्री करना अधिक लाभप्रद होगा परन्तु बढ़े हुए आयातों के ही कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्री कर पाने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने केवल कानून के अनुसार लैब के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ताकि वे बढ़े हुए आयातों की स्थिति में समायोजना कर सकें।

(थ) एचयूएल ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्वयं के कारण है और यह अंतर्भूत अकुशलता और अपर्याप्त पुनर्संरचना योजनाओं के कारण है। घरेलू उद्योग ने विभिन्न पुनर्संरचना एवं समायोजन योजनाओं को अभिज्ञात किया है ताकि आयातों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की वांछनीयता एवं आवश्यकता का इस संदर्भ में आकलन एवं निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजन किए जा रहे हैं और वह प्रतिस्पर्धी बन रहा है।

वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने पहले ही समायोजन संबंधी अपनी योजना को अभिज्ञात कर लिया है और रक्षोपाय शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है ताकि वह बढ़ते हुए आयातों से होने वाली गंभीर क्षति से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने में समर्थ हो सकें। इसके अलावा घरेलू उद्योग इस तथ्य से भी भली भाँति अवगत है कि रक्षोपाय अस्थाई और अल्पावधिक होते हैं जिन्हें घरेलू उपादकों की सुरक्षा हेतु केवल इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि वे पुनः समायोजन कर सकें और बढ़ते आयातों से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।

VI. मै. फेना (प्रा.) लि०, नई दिल्ली, एडवांस सर्फैक्टेंट्स इंडिया लि. नई दिल्ली, ए. आर. स्टैनकम प्रा लि०, कोलकाता, न्यू इंडिया डिटर्जेंट्स लि. नई दिल्ली, सैल्वेज सर्फैक्टेंट्स (प्रा.) लि. कानपुर, साई सल्फोनेट्स प्रा. लि. कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लि. कोलकाता, स्मॉल स्केल डिटर्जेंट्स एण्ड सोप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, कोलकाता एवं स्टैंडर्ड सर्फैक्टेंट्स लि., कानपुर के निवेदनों के उत्तर में याचिकाकर्ताओं ने निम्नानुसार विवरण दिया:

क. इन आयातकों ने महानिदेशक के समक्ष आयातक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है। अतः आयातकों के वर्तमान निवेदकों को नजरअंदाज करना उचित होगा क्योंकि घरेलू उद्योग को इन निवेदनों पर खंडशः अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस उपाय से निश्चित रूप से जाँच प्रक्रिया में बाधा आती है और यह घरेलू उद्योग के हितों के लिए पक्षपातपूर्ण है।

ख. जहाँ तक कथित रूप से पुराने आयात आँकड़ों का संबंध है यह कहा गया है कि यद्यपि दिए गए तर्क सैद्धांतिक रूप में अच्छे हैं परंतु उनका कोई कानूनी अथवा तार्किक आधार नहीं है।

ग. ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिससे ऐसा संकेत मिलता हो कि जांच के प्रारंभ होने से तत्काल पहले की अवधि पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यू.एस. लाइन पाइन मामले में (अर्जेंटीना फुटवियर(ईसी) मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसरण में) डब्ल्यू टी ओ पैनल का मत था कि इस शब्द "हाल में" का तात्पर्य भूतलक्षी विश्लेषण के किसी स्वरूप से है। इसका तात्पर्य प्राधिकारी के निर्णय के तत्काल पहले की स्थितियों के विश्लेषण से नहीं है।

घ. यदि जाँच में प्रारंभ होने के पश्चात् जांच अवधि में लगातार संशोधन किया जाता है तो इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे जांच एक कभी न समाप्त होनी वाली प्रक्रिया बन जाएगी।

ङ. आयातकों ने यह संकेत नहीं दिया है कि प्रस्तावित जांच अवधि के पश्चात् स्थितियों में किस प्रकार उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। केवल एक वक्तव्य कि कीमतों में परिवर्तन हुआ है, जाँच के प्रयोजनार्थ निर्धारित जांच अवधि की पड़ताल हेतु पर्याप्त नहीं है। यह हमारे इस तर्क के प्रति पूर्वाग्रह रहित है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनंतिम शुल्कों के प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण स्थितियों संबंधी मुद्दे की जांच को छोड़कर केवल जांच अवधि से संबंधित सूचना पर विचार किया है।

च. घरेलू उद्योग ने जुलाई 2008 में घरेलू उद्योग के पास नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के साथ याचिका दायर की है और अतः निवेदन में कोई सार नहीं है।

छ. एक उच्च एन आई पी (प्रस्तावित जांच अवधि के कारण) से संबंधित संशय निराधार है क्योंकि कम कीमत पर बिक्री के प्रयोजनार्थ की जाने वाली तुलना हमेशा समान अवधि में होने वाले आयातों से की जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि आयातक इस प्रकार के तुच्छ मुद्दे उठाकर केवल अनंतिम शुल्क के लागू किए जाने में विलम्ब अथवा रूकावट उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं।

ज. वाणिज्य मंत्रालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल ही में ऐसी कई जांचें प्रारंभ की हैं जहां आयात आंकड़े नौ महीने से अधिक अवधि के हैं। इस संदर्भ में, आर टी एम ए बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ([2002 (149)ई एल टी 45 (राज.)] के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। यद्यपि वह निर्णय पाटनरोधी जांच के संदर्भ में दिया गया है तथापि वह अनुपात काफी हद तक रक्षोपाय संबंध जांचों पर भी लागू होता है क्योंकि संगत प्रावधान बिल्कुल समान हैं।

झ. यदि आयातकों के इस तर्क को स्वीकार किया जाता है कि घरेलू उद्योग को वित्तीय वर्ष 2008-09 की तीन तिमाहियों की सूचना देनी चाहिए, तो यह आयातकों द्वारा थोपे गए ऐसे निर्देश के समान होगा कि किसी कानूनी, तथ्यात्मक अथवा तार्किक आधार के बिना जांच अवधि का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए।

ञ. जांच अवधि में कोई संशोधन, जो कानूनी रूप से आवश्यक न हो, वह घरेलू उद्योग जो पहले से ही बढ़ते आयातों के कारण क्षति का सामना कर रहा है, के हितों के लिए अहितकर होगा।

ट. विभिन्न मानदण्डों के विश्लेषण से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को बढ़ते आयातों के कारण गंभीर क्षति हुई है। देश में खपत की तुलना में आयातों में समग्र एवं तुलनात्मक रूप से भी वृद्धि हुई है जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार हिस्से के एक प्रमुख भाग का स्थान सस्ते आयातों ने ले लिया है।

ठ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2007-08 में अत्यधिक गिरावट आई है। अधिकांश कंपनियों को बढ़ते आयातों के कारण दबाव के साथ-साथ पूर्ववर्ती लाभों में हानि की स्थिति एवं लगाई गई पूँजी पर अपर्याप्त आय के कारण अल्प क्षमता उपयोग का सामना करना पड़ा था। कम कीमतों पर बढ़ते आयातों एवं घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। आयातों में वृद्धि से, कीमतों में दबाव एवं घरेलू उद्योग द्वारा विक्रय की गई मात्रा में कमी के संदर्भ में क्षतिकारी प्रभाव पड़ा है।

## 11. महानिदेशक के जांच परिणाम

मैंने मामला रिकॉर्डों एवं हितबद्ध पक्षों एवं घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर की सावधानीपूर्वक पड़ताल की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन एवं उनसे उठने वाले मुद्दों पर निम्नलिखित जांच परिणाम में समुचित स्थानों पर विचार किया गया है:-

### I. प्रारंभिक जांच परिणाम को जारी किया जाना और प्राकृतिक न्याय का अनुपालन

तत्काल रक्षोपाय लागू किए जाने संबंधी मुद्दों की जांच की गई थी। यह पाया गया है कि दिनांक 29/03/2005 से 12/11/2008 की अवधि के दौरान डब्ल्यूटीओ को कुल 168 रक्षोपाय संबंधी जांच परिणाम सूचित किए गए हैं। यह पाया गया है कि इनमें से 15 मामलों में, रक्षोपाय जांच की शुरुआत के 30 दिनों के भीतर अनंतिम रक्षोपाय की सिफारिश की गई है/को लागू किया गया है। कुछेक मामलों में जांच प्रारंभ होने की तारीख को ही अनंतिम रक्षोपायों की सिफारिश कर दी गई थी। दिनांक 29/07/1997 की अधिसूचना सं० 35/97-एनटी-सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित सीमाशुल्क टैरिफ के नियम 9 (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में यह निर्दिष्ट है कि महानिदेशक जांच के संचालन हेतु त्वरित कार्रवाई करेंगे और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में वह गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। जांच को शासित करने वाले सिद्धांत सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) के नियम 6 में दिए गए हैं, जो नियम 9 से अलग हैं। सीमाशुल्क टैरिफ/नियमावली के नियम 15 (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) में इस स्थिति में अधिमानी रक्षोपाय शुल्क की वापसी का प्रावधान है, यदि जांच समाप्त होने के पश्चात लगाए गए रक्षोपाय शुल्क, पूर्व में लगाए एवं वसूले गए अनंतिम शुल्क से कम हों। उक्त नियमावली के नियम 6, 9 एवं 15 के सुमेलीकृत पठन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नियमावली में प्रारंभिक जांच परिणाम एवं अधिमानी शुल्क की वापसी के आधार पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की त्वरित सिफारिश का प्रावधान है बशर्ते यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राकृतिक न्याय के पश्चात, जैसा कि नियम 6 में निहित है जांच समाप्त होने के पश्चात लगाया गया शुल्क अनंतिम रक्षोपाय शुल्क से कम है। तथापि, महत्वपूर्ण स्थितियों में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को लागू करने में विलम्ब से क्षति हो सकती है जिसको सुधारना मुश्किल हो सकता है। तदनुसार मेरा विचार यह है कि जांच परिणाम जारी करना और अनंतिम शुल्क लागू करना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से पूर्णतः संगत है।

### II कुछेक विशिष्ट सूचनाओं की गोपनीयता:

एच यू एल के प्रतिनिधियों का यह तर्क था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुचित एवं अत्यधिक गोपनीयता के दावों से हितबद्ध पक्षकारों को अर्थपूर्ण निवेदन करने के अधिकार को गंभीर क्षति हुई है। उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी से याचिकाकर्ताओं को सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं विशेषकर आयातक सहित हितबद्ध पक्षकारों को योजनाओं की पुनः संरचना संबंधी सभी व्योमों को प्रकट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। मैंने आवेदकों द्वारा गोपनीय दस्तावेजों के रूप में सीपी गई पुनः संरचना संबंधी

योजना की जांच की है और यह पाया है कि पुनः संरचना संबंधी योजना विस्तृत, विशिष्ट और तकनीकी एवं आर्थिक मानदण्डों पर आधारित है। एक बार पक्षोपायों की अवधि समाप्त हो जाने पर पुनः संरचना योजना को ही आयातों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने वाला माना गया है। एक पुनः संरचना योजना का आशय निपुणता लाना होता है और यह तुलनात्मक निपुणता ही है जो प्रतिस्पर्धात्मकता उत्पन्न करती है। पुनः संरचना योजना एक बौद्धिक संपदा है और योजना की यह गोपनीयता ही पुनः संरचना के कारण होने वाले परिवर्तनों का प्रबंधन करने में सहायता करती है। इसके अलावा, गोपनीयता प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने में सहायता करती है।

तथापि, मैं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रभावी खण्डन एवं निर्णय लेने में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछेक सूचना का प्रकटन करने की आवश्यकता को उचित समझता हूँ। दो प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सुसंगत संतुलन को बनाए रखने के लिए, मैंने प्रारंभिक जांच परिणामों में गोपनीय मानी गई सूचना और साथ-साथ मेरे विचार से जिस सूचना के प्रकटन से गोपनीयता का दावा करने वाले पक्ष के हितों को गंभीर क्षति पहुंचेगी, को छोड़कर सभी संगत सूचनाओं का प्रकटन किया है।

III. उत्पाद: जांचाधीन उत्पाद "ऑल लीनीयर एल्किल बेंज़ीन, मिक्स्ड एल्किल बेंज़ीन" है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची 1 के उपशीर्ष सं. 38170011, आई टी सी के उपशीर्ष सं. 38170011 तथा एच एस एन की उपशीर्ष सं. 38170011 के तहत वर्गीकृत है। जांच की विषय वस्तु केवल मिक्स्ड एल्किल बेंज़ीन और लीनीयर एल्किल बेंज़ीन है न कि मिक्स्ड एल्किल नेथालीन्स। उपर्युक्त उत्पाद को वाणिज्यिक बाजार की भाषा में सामान्यतः "लीनीयर एल्किल बेंज़ीन" (संक्षिप्त में "एल ए बी") के नाम से जाना जाता है।

घरेलू उद्योग लीनीयर एल्किल बेंज़ीन के उत्पादन हेतु कच्ची समग्री के रूप में केरोसीन (निस्सारित - सी 10 - सी 13 पैराफिन्स) एवं बेंज़ीन का उपयोग करता है। सी 10 - सी 15 पैराफिन्स को फीडस्टॉक केरोसीन से हाइड्रोबोन मोलेक्स प्रक्रिया द्वारा निस्सारित किया जाता है। इन पैराफिनों को उच्च ताप पर चयनात्मक डिहाइड्रोजेनेशन द्वारा उनके ओलेफिन्स में परिवर्तित किया जाता है। सी 10 - सी 13 ओलेफिनों को एल्किलीकृत करके बेंज़ीन बनाया जाता है जिससे लीनीयर एल्किल बेंज़ीन बनता है। सी 10 - सी 13 लीनीयर ओलेफिन्स से उत्पादित लीनीयर एल्किलबेंज़ीन उपयोगी डिटर्जेंट मध्यवर्ती होते हैं और उन्हें सरलता से सल्फोनेट करके लीनीयर एल्किलबेंज़ीन सल्फोनेट्स बनाया जा सकता है। ये यौगिक घरेलू डिटर्जेंट के "सक्रिय" घटक होते हैं। वे सर्फेस एक्टिव यौगिक (सर्फैक्टेंट्स) होते हैं जिन्हें विभिन्न विनिर्मितियों (अक्सर अकार्बनिक साल्ट्स) के साथ संयोजित करके डिटर्जेंट बनाया जाता है। संक्षिप्त में एल ए बी का उपयोग डिटर्जेंट उद्योगों द्वारा एक महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में किया जाता है।

IV. घरेलू उद्योग: वर्तमान जांच में 0 रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० मुम्बई, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० चेन्नई, निरमा लि. अहमदाबाद द्वारा दायर आवेदन पर शुरू की गई है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. नई दिल्ली द्वारा समर्थित है इन कंपनियों के हिस्से निम्नानुसार हैं :-

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कम्पनी	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा
इंडियन ऑयल	11%	24%	26%	28%
निरमा	26%	21%	19%	19%
रिलायंस	40%	38%	36%	37%
टीपीएल	23%	18%	19%	17%
कुल	100%	100%	100%	100%

इंडियन ऑयल को छोड़कर समर्थन करने वाले आवेदकों का हिस्सा वर्ष 2007-08 के दौरान 72% रहा है और जब इंडियन ऑयल को भी आवेदकों में गिना जाता है तो हिस्सा 100% बनता है। तदनुसार आवेदक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8ख की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग है।

#### V. अप्रत्याशित घटनाक्रम:

(क) गैट 1994 की धारा XIX निम्नानुसार है:-

1 (क) "अप्रत्याशित घटनाक्रमों और इस करार के तहत किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा लिए गए दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप "अप्रत्याशित घटनाक्रम" शब्द का उपयोग किया जाता है।" बहुवचन में "घटनाक्रमों के इस्तेमान का तात्पर्य यह है कि घटनाक्रम एक से अधिक हो सकते हैं जिनके संयोजित प्रभाव पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रायोगिक तौर पर यह आवश्यक नहीं कि सभी घटनाक्रम स्वतंत्र हो और वास्तव में ऐसे घटनाक्रम एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह ऐसे भी घटनाक्रमों के अनुनाद का प्रभाव ही है जो व्यापार की गतिशीलता पर प्रभाव डालते हैं और उनके कारण परिणामों में परिवर्तन हो सकता है। अतः अप्रत्याशित घटनाक्रमों और उनके परिणामों पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाए।

(ख) प्रारंभिक जांच परिणामों से यह संकेत मिलता है कि अधिकांश एल ए बी रिपोर्टें मध्य पूर्व (कतर, ईरान एवं सउदी अरब) से आ रही हैं जहाँ अतिरिक्त क्षमताएं उत्पन्न हुई हैं। इन देशों में लगभग 70% क्षमताओं का उपयोग निर्यात बाजार में किया जाता है। यह देखा गया है कि भारत में वर्ष 2007-08 में अच्छी वृद्धि प्रदर्शित हुई थी और यह वर्ष 2008-09 में भी जारी है। वृद्धि की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ कई विकसित देशों ने मंदी के आगमन की घोषणा कर दी है वहीं भारत में वृद्धि जारी है।

प्रति व्यक्ति अधिक खपत वाले विकसित देशों में माँग में अवरुद्धता के कारण उद्योग स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों की ओर उन्मुख होता है जहाँ माँग होती है और माँग में वृद्धि होती है। व्यापार की परिस्थितियों में परिवर्तन, विदेशों में बेशी क्षमताओं के सृजन जैसी अन्य स्थितियों के साथ-साथ विश्व भर में हुए परिवर्तनों का मिश्रित प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसका पूर्वानुमान लगाना कठिन था और जिसके कारण आयातों में वृद्धि और तदुपरांत क्षति हुई।

## VI. बढ़े हुए आयात

(क) निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि 2006-07 की अवधि की तुलना में वर्ष 2007-08 में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में आयात वर्ष 2005-06 की तुलना में बहुत अधिक थे। वृद्धि का यह रुझान सितंबर 2008 तक जारी रहा है।

(ख) घरेलू उत्पादन के साथ-साथ घरेलू बिक्री की तुलना में आयातों में सापेक्ष वृद्धि का अध्ययन किया गया है और यह पता चला है कि घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों का हिस्सा वर्ष 2006-07 में 7.25% की तुलना में वर्ष 2007-08 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 14.27% हो गया है। बाद के महीनों में भी यही रुझान जारी रहा है। वर्ष 2007-08 में भारत में कुल बिक्री में आयातों का हिस्सा 7.22% से बढ़कर 13.91% हो गया और तदुपरांत भी यही रुझान जारी रहा जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

भारत में एलएबी का आयात			
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु. में)	कीमत (प्रति मी. टन रु. )
2004-05	9854	3913	39710
2005-06	4871	2314	47506
2006-07	21470	11491	53521
2007-08	45505	25474	55981
अप्रैल 2007- सित. 2008 (18 महीने)	70506	47652	67586
अप्रैल 2007- सित. 2008 (वार्षिक)	47004	31768	67586

घरेलू उद्योग की तुलना में आयात में वृद्धि					
	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल 07- सित. 08 (18 महीने)	अप्रैल 2007- सित. 2008 (वार्षिक)
घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों का हिस्सा	1.69%	7.25%	14.27%	14.55%	14.55%
घरेलू उत्पादन का हिस्सा (कुल)	98.31%	92.75%	85.73%	85.45%	85.45%
कुल घरेलू बिक्री की तुलना में आयातों का बाजार हिस्सा	1.73%	7.22%	13.91%	14.40%	14.40%
घरेलू बिक्री का हिस्सा	98.27%	92.78%	86.09%	85.60%	85.60%



(ग) इसके अतिरिक्त उपयुक्त आरओसीई लेते हुए बिक्री लागत और आसन्न कीमतों की तुलना से यह पता चला है कि आयात न्यूनतर कीमतों पर हुए हैं। तदनुसार मैंने पाया कि आयातों में सापेक्ष एवं तुलनात्मक रूप में वृद्धि हुई है और विगत अवधि के दौरान आयातों में हुई वृद्धि अत्यधिक है।

**VII. गंभीर क्षति :** इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, मैंने निम्नलिखित पैराग्राफों में रक्षोपाय नियमों के अनुबंध के पैराग्राफ 1 के तहत परिकल्पित कारकों सहित अनेक कारकों की जाँच की है :

(क) **घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्सा :** विचाराधीन अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई है। सकल घरेलू उद्योग (आईओसीएल सहित) का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 98% से घटकर जाँचाधीन अवधि में 12% की कमी दर्ज करते हुए लगभग 86% रह गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007-08 की अवधि के दौरान बाजार में 16% से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 की तुलना में अप्रैल, 07 से सितंबर, 2008 (वार्षिक) के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा लगभग 5% घटकर 9083 मी. टन रह गई थी। इसके अतिरिक्त इस तथ्य कि भारतीय बाजार की कुल माँग और आकार बढ़कर 45589 मी. टन तक पहुँच गया है जो लगभग 16% की वृद्धि दर्शाता है, के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में कमी आई है।

घरेलू बाजार का हिस्सा					
	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल 07- सित. 08 (18 महीने)	अप्रैल 2007- सित. 2008 (वार्षिक)
आयात	4871	21470	45505	70506	47004
घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों का हिस्सा	1.69%	7.25%	14.27%	14.55%	14.55%
घरेलू उत्पादन का हिस्सा (कुल)	98.31%	92.75%	85.73%	85.45%	85.45%
कुल घरेलू बिक्री की तुलना में आयातों का बाजार हिस्सा	1.73%	7.22%	13.91%	14.40%	14.40%
घरेलू बिक्री का हिस्सा	98.27%	92.78%	86.09%	85.60%	85.60%

(ख) **क्षमता का उपयोग और उत्पादन :** जहाँ वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2007-08 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी आई है वहीं विगत वर्ष की तुलना में नगण्य (0.027%) वृद्धि भी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि क्षमता उपयोग आधार वर्ष में 104% की तुलना में गिरकर अप्रैल 2007-सितंबर 2008 की अवधि के दौरान 96% हो गया है। यह बाजार आकार में लगभग 18% की वृद्धि के बावजूद हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उत्पादक बढ़ते बाजार का उचित हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल 07- सित. 08 (18 महीने)	अप्रैल 2007- सित. 2008 (वार्षिक)
संस्थापित क्षमता	सूचीबद्ध	448500	448500	497338	746007	497338
वास्तविक उत्पादन		467765	459192	470331	716613	477742
क्षमता उपयोग		104%	102%	95%	96%	96%

(ग) **उत्पादकता** : ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे यह स्पष्ट हो कि उत्पादकता की कमी के कारण क्षति हुई है।

(घ) **लाभप्रदता** : वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2007-08 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक कमी आई है। वर्ष 2005-06 में घरेलू उद्योग को हुए प्रति मी. टन 100 रु. (सूचीबद्ध) के लाभ की तुलना में वर्ष 2007-08 में प्रति मी. टन 41 रु. (सूचीबद्ध) की हानि हुई है। वर्ष 2005-06 में प्रति मी. टन 100 रु. (सूचीबद्ध) के लाभ की तुलना में वर्ष 2007-08 में प्रति मी. टन 42 रु. (सूचीबद्ध) की हानि हुई है। घरेलू उद्योग के लाभ/हानि की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है :

(ङ.) **रोजगार** : रोजगार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा सभी भारतीय उत्पादकों के बहु-उत्पाद कंपनी होने और मौजूदा श्रम कानूनों के कारण है। तथापि घरेलू उद्योग का मानना है कि यदि वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं आया तो रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना आसन्नवर्ती है।

(च) **कीमत विश्लेषण** : पहुँच मूल्य और वर्तमान निवल बिक्री आय के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लगभग 6% की सीमा तक कीमत कटौती हुई है। यह भी पाया गया कि लगभग 22% तक कम कीमत पर बिक्री के कारण घरेलू उद्योग को हानि हो रही है।

सभी संगत मानदंडों के विस्तृत मूल्यांकन से यह प्रदर्शित होता है कि एलएबी के घरेलू उद्योग को समग्र रूप से हानि हुई है। कुछेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों को उनकी वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार लाभ हो रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्लोपाय नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों का मूल्यांकन अपेक्षित है न कि समग्र रूप से कंपनी के लिए। अतः इस संबंध में प्रस्तुत किए गए तर्क का कोई औचित्य नहीं है।

8. **कारणात्मक संबंध** : वर्ष 2004-05 से वित्त वर्ष 2007-08 के अंत तक की अवधि के लिए ऊपर किए गए उल्लेखानुसार मानदंडों के विस्तृत मूल्यांकन से एलएबी के भारतीय उत्पादकों को हुई गंभीर क्षति अथवा हानि प्रदर्शित होती है। जैसाकि ऊपर चर्चा हुई है, वर्ष 2007-08 के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अत्यधिक कमी आई है। उसी अवधि में विभिन्न देशों में निर्यातोन्मुखी क्षमताओं के चालू होने और बढ़ते भारतीय बाजार के कारण सापेक्ष और तुलनात्मक

दोनों रूपों में आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संयोग से वर्ष 2005-06 की अवधि की तुलना में वर्ष 2006-07 और 2007-08 की अवधि के दौरान जब लाभप्रदता में कमी आई उसी समय आयातों में भी वृद्धि हुई। आयातों में वृद्धि के साथ-साथ क्षमता उपयोग में भी गिरावट पाई गई। यह कम कीमतों पर आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के बीच प्रत्यक्ष सहसंबंध का द्योतक है और कीमतों पर दबाव तथा घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की गई मात्रा में कमी के रूप में आयातों में वृद्धि के गंभीर परिणाम सामने आए।

**IX. समायोजन योजना :** घरेलू उत्पादकों ने लागत पर हुए अनुमानित प्रभाव सहित एक विस्तृत समायोजना योजना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा इन उपायों के माध्यम से (i) गत्यावरोध दूर करने (ii) ऐसी अवरुद्ध क्षमताओं हेतु फीडस्टॉक आपूर्ति सुनिश्चित करने, आदि सहित अनेक निर्णयों द्वारा क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग करने के लिए उपाय किए गए हैं। उपर्युक्त उपायों के अनुसार क्षमताओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रचालन लागतों का अनुकूलतम उपयोग होने की संभावना है। चूंकि ये गत्यावरोध दूर करने से संबंधित प्रचालन हैं अतः निर्धारित क्षमताओं में थोड़ी वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग का प्रत्येक सदस्य पुनर्संरचना के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहा है। पुनर्संरचना योजनाओं के प्रारंभिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि ये योजनाएँ व्यवहार्य हैं।

**X. अन्य मुद्दे :** प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि डिटर्जेंट उद्योग में हजारों लघु इकाइयाँ, के वी आई सी इकाइयाँ, लघु स्तरीय उद्योग, कुछेक मध्यम और बड़े स्तर के विनिर्माता शामिल हैं और यह पाँच लाख से अधिक कामगारों को रोजगार देता है जबकि एलएबी उद्योग में चार बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं और यह केवल 500 कामगारों को रोजगार देता है। इसके अतिरिक्त मात्र एलएबी ही डिटर्जेंट उत्पादों के कच्चे माल की लागत का 50 से 60% हिस्सा है। कुछ एलएबी का प्रयोग निर्धन किसानों द्वारा कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों और इमल्सिफायर जैसे अन्य उत्पादों तथा टेक्सटाइल उद्योग आदि में इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्सटाइल पूरक जैसे अन्य रसायनों के विनिर्माण के लिए भी किया जाता है। दूसरी ओर एलएबी के चार घरेलू विनिर्माताओं में से फॉरच्यून 500 कंपनियों में शामिल हैं जिनके लिए एलएबी व्यापार बिल्कुल नगण्य हैं अर्थात् उनके कुल व्यवसाय के 1% से भी कम है। यद्यपि स्लोपाय शुल्क लागू किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में आयातित एलएबी की लागत में वृद्धि हो सकती है, तथापि स्लोपाय कानून के प्रमुख उद्देश्य, जो बढ़े हुए आयातों की स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक समायोजनों हेतु घरेलू उद्योग को पर्याप्त समय प्रदान करना है, को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नोट करना आवश्यक है कि स्लोपाय शुल्क लागू किए जाने से घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा में बने रहने में सक्षम होगा और साथ ही प्रयोक्ताओं/क्रेताओं के पास अपनी सामग्री संबंधी आवश्यकताओं के लिए भरपूर विकल्प होंगे और वह भी प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर।

**XI. संकटकालीन स्थितियाँ :** घरेलू बाजार में क्षतिकारक कीमतों पर आयातों के हिस्से में वृद्धि अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता और वस्तुसूची की हानि का न्यूनतम करने के लिए क्षमताओं का अप्रयुक्त रहना वे संकटकालीन परिस्थितियाँ हैं जिनके लिए प्रारंभिक परिणाम जारी किए जाने चाहिए क्योंकि विलंब के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना कठिन होगा।

**XII. विकासशील देश :** निम्नलिखित तालिका में निर्यातक देशों से आयातों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ईरान (24%), मलेशिया (4%), कतर (37%), सऊदी अरब (16%) से आयात हुए हैं जो 3% से अधिक हैं। अन्य सभी विकासशील देशों से हुए उत्पाद का कुल निर्यात भारत को हुए निर्यात के 9% से अधिक नहीं है। तदनुसार ईरान, मलेशिया, कतर तथा सऊदी अरब को छोड़कर दिनांक 14.12.1998 की अधिसूचना सं. 103/98-सीमाशुल्क (यथासंशोधित) द्वारा यथा अधिसूचित सभी विकासशील देशों से एलएबी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।

तालिका

वर्ष 2007-08 स्रोत आईबीआईएस				
		मात्रा (मी. टन)	मूल्य	कुल आयातों में % हिस्सा
			(लाख रु. में)	(मात्रा)
थाइलैंड		14	14	0%
ईरान		10696	5937	24%
नीदरलैंड		1007	527	2%
कोरिया गणराज्य		14	14	0%
मलेशिया		1805	1054	4%
कतर		16661	9676	37%
सऊदी अरब		7122	3877	16%
संयुक्त अरब अमीरात		103		0%
स्विट्जरलैंड		8083		18%
कुल		45505	25474	

11. निष्कर्ष तथा सिफारिश : उपर्युक्त प्रारंभिक परिणामों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि एलएबी के आयातों में वृद्धि से एलबी के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है। यहाँ संकटकालीन स्थितियाँ, जिसमें रक्षोपाय लागू करने में किसी भी प्रकार के विलंब से हुई क्षति की भरपाई कठिन होती है, मौजूद हैं जिसके कारण गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे का अंतिम निर्धारण करने से पूर्व 200 दिन की अवधि के लिए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को तत्काल लागू किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू उत्पादकों द्वारा एलएबी की औसत उत्पादन लागत (गुप्त), नियोजित पूँजी पर समुचित आय, आयात शुल्कों के वर्तमान स्तर और ~~रक्षोपाय~~ की औसत आयात कीमतों को ध्यान में रखते हुए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 38170011 के अंतर्गत आने वाले लीनियर एलकाइल बेंजीन के आयातों पर मूलानुसार **20%** की दर से रक्षोपाय शुल्क, जिसे घरेलू उद्योग के हित की रक्षा के लिए न्यूनतम रूप से आवश्यक माना गया है, लागू किए जाने की सिफारिश की जाती है।

**12. आगे की प्रक्रिया :**

(i) अंतिम निर्णय से पूर्व उचित समय में एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी जिसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी।

[फा. सं. डी-22011/23/2008]

एस. एस. राणा, महानिदेशक

**DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2009

**Sub: Safeguard investigation concerning imports of Linear Alkyl Benzene - Preliminary findings.**

**G.S.R. 63(E).**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty), Rules, 1997 thereof;

**1 Procedure:** The Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Linear Alkyl Benzene (LAB) into India was issued on 19th December, 2008 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day. A copy of the Notice was also sent to all known interested parties as under:

**2 Domestic Producers**

- (i) M/s. Reliance Industries Ltd., Mumbai,
- (ii) M/s Tamilnadu Petroproducts Ltd., Chennai,
- (iii) M/s Nirma Ltd., Ahmedabad
- (iv) M/s Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi (Supporter)

**3 Importers**

- (i) Fena Pvt Ltd, A-67&68 Mettupalayam, PIPDIC Industrial Area, Pondicherry, 605009
- (ii) Skill Dychem, Village Panchpara, PO Radhadasi- 711309, Howrah, West Bengal
- (iii) Sai Sulphonates P Ltd, 21, Princep Street, Kolkata 700072, West Bengal
- (iv) Rohit Surfactants Pvt Ltd. (GHARI), KDC- Chaubepur unit, 117/H-2/202, Pandu Nagar, Kanpur- 200005, Uttar Pradesh

**4 Exporters**

- a) Iran Chemicals Industries Investment Companies, No.91 Saidi St Africa Ave Teheran ( 19679 ) Iran .
- b) Gulf Farabi Petrochemical Co. Al-Jubail Industrial City 31961, P.O. Box 11763, Kingdom Of Saudi Arabia
- c) Seef Limited, Qatar, Seef Limited, Post Box: 50077, Mesaieed, State Of Qatar
- d) Kolmar Group Ag, Laubehof, Metallstrasse 9, 6300 Zug, Switzerland

**5** A Copy of the Notice was also sent to government of exporting countries through their embassies in New Delhi.

**6** Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and they were asked to submit their response within 30 days.

- 7 The domestic industries submitted the response to the questionnaire.
- 8 Indian importers M/s Fena Pvt. Ltd, New Delhi, Sai Sulphonates Pvt Ltd, 24 Pargnas and Rohit Surfactants Pvt Ltd, Kanpur and exporters Gulf Farabi Petro Chemical, Kingdom of Saudi Arabia and Seef Ltd, Quatar submitted preliminary objections and sought more time to submit detailed replies.
- 9 24 manufacturers of soaps and detergents from all over India, both large scale and small scale, applied to be treated as interested parties and sought more time to file detailed replies. Director General after due consideration agreed to include 24 manufacturers of soaps and detergents as interested parties and also allowed extension of time till 06/02/2009. The extension of time till 06/02/2009 was also granted to original noticees as well on request. The name address of the 24 new "Interested Parties" are given below

Sl.No	Name and address of the respondents
1	Fashion Suiting (P) Ltd. 3, Chhabra Mansion, Puri Road, Bhilwara-311001
2	Shree Unicon Organics Pvt. Ltd. BS, Apjee, 130 Mumbai Samachar Marg Mumbai-400023
3	A.R Salphonates Pvt. Ltd. Plot No. N41 Additional Ambernath, MIDC Anand Nagar, Dist.Thane - 421501 Maharashtra
4	Tamil Nadu Small Scale Soap & Detergents Chateau 'D Ampa, IV Floor, No37, Old No. 110 Nelson Manickam Road, Chennai-600029
5	Shanati Nath Detergents (P) Limited P-15, Kalakar Street, Kolkata-700007
6	Rajaram Group of Industries 14, Azeez Nagar IInd Street, Kodambakkam, Chennai.600024
7	Kishors Sons Detergents Pvt. Ltd. 15-9-469, Mahanoongunj, Hydrerabad - 500012. (A..P.) India
8	Hindustan Uni Leaver Economic Laws Practiqe, Advocate and Solicitors, 1502, Dalamal Towers, Nariman Point, Mumbai 400021
9	Advance Surfactants India Limited 511/2/1. Rajokri, New Delhiu-110038
10	A.R. Stanchem Pvt. Ltd., Exporters & Manufacturers Old Court House Street, 2nd Floor, Coke & Kalvay Building Kolkata 70000-1
11	New India Detergents Limited A-2/25 Model Town -1, Delhi-110009
12	M/s Small Scale Detergents 43 European Asyum Lanae, Kolkata -700016
13	Standards Surfactants Ltd

	8/5 Arya Nagar, Kanpur-208002
14	Gora Mal Hari Ram Ltd. 39, Najafgarh Road, Ind Area, New Delhi- 110015
15	Detergents Manufacturers Associations 148 New Okhla, Industrial Complex-I, New Delhi-110020
16	Barkur Surfactants Pvt. Ltd. Unitop House , East West Estate , Safed Pool, Andhari Kurla Road Mumbai-400072
17	ISRO Product Unitop House , East West Estate, Safed Pool, Andhari Kurla Road Mumbai-400072
18	S. Kumars Detergents Pvt. Ltd 4-D, Local Shopping Centre ,A Block , Ring Road, Naraina , New Delhi-110028
19	Saci- Chem 59 & 60 DSIDC, Industrial Complex , Okhla , Phase-I, New Delhi-110020
20	Hipollin Limited , Madhuban , 4th Floor , Ellis bridge, Ahmedabad -380006
21	All India Federation of Detergents Manufacturers Delhi
22	Maharashtra Small Scale Soap Detergents Manufacturers Association Mumbai
23	Gujrat Small Scale Detergents Ahmedabad
24	Power Soaps Ltd 62-B, North Boag Road, T. Nagar, Chennai-600017

- 10 The application, submissions by interested parties and additional submissions by applicants, which are other than confidential, have been kept in the Public File. The views of the Domestic Industry, importers and other interested parties are summarized below:

**I. The Domestic Industry of LAB have made following major points:**

- a. The product is defined as "All Linear Alkyl Benzene, Mixed Alkyl Benzene falling under the tariff description of Customs Heading 3817 00 11. The above product is generally known as 'Linear Alkyl Benzene' (for short "LAB") in commercial market parlance. The subject goods are used for manufacture of Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid or the Sodium Salt of Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid. All Linear Alkyl Benzene and the subject goods have been classified under chapter heading 38.17 of the Customs Tariff Act, 1975.



- b. The period of investigation (POI) is April 2007 to March 2008 (12 Months). The information for the post period of investigation period (to the extent readily available) has also been provided on January 22, 2009 with reference to the DG's office letter dated 2nd January, 2009 and 7th January, 2009, primarily to establish the case for immediate imposition of provisional duties.
- c. The imports have increased not only in absolute terms but also in relation to the production and demand.
- d. A great majority of LAB imports coming to India are from Qatar, Iran and Saudi Arabia. Roughly 70% of the combined capacities of LAB in these countries and other Middle East countries are earmarked for exports. The geographical proximity of these countries combined with the strong LAB downstream sector in India, provides a huge attraction for these countries to direct their exports to India. The capacity is likely to go further up with another plant starting up in Egypt in 2007. It is therefore seen that the increase in production capacity clearly increased pressure on countries in this Region to export very large quantities of LAB (and indeed the exports from these countries increased almost five times in 2006-2007 when compared to 2005-06 and this surge continued throughout Calendar Year 2007). For most of these countries exports as a share of their total production increased during 2006-07 and even during 2007-08.
- e. It is also reported that the consumption of LAB in traditional markets such as the US and the EU market has stagnated or are steadily declining. On the other hand, India presented a sizeable market for LAB with a robust growth. These factors provided an incentive for the exporting country to ship increasing quantities of LAB at low prices.
- f. The share of imports increased appreciably from 3% to 14%. Imports from various countries, and mainly from the Middle East Region, are coming at extremely low prices. The average net sales realization of the domestic industry has increased over the injury investigation period. However, this increase in the average net sales realization of the domestic industry can be attributed as the direct result of increase in the cost. The cost/MT of the domestic industry has increased by about 33% during the POI as compared to the base year. However, it may be seen that the average selling price of the domestic industry has increased only by about 23% during the same period. Thus, the increase in the selling price of the domestic industry has not been commensurate with the increase in the cost of production.
- g. The sales volume of the domestic industry fell by about 14% during the above-mentioned period. This is a clear indication that a major portion of the market share of the domestic industry has been taken away by imports.

- h. The average unit value of imports from the major exporting countries has not raised in tune with the change in international feedstock prices as is evident the petitioners were not able to hold on to their market share without dropping prices.
- i. The profitability of the domestic industry has declined substantially during the POI as compared to the base year i.e., 2004-2005 due to current severe undercutting and underselling by the exporting country despite suppressed prices of domestic industry.
- j. The imports from most of the sources have undersold the domestic industry product during POI. It is becoming very difficult for the petitioners to operate at present and the survival of the domestic industry is equally becoming difficult. The subject imports were able to gain significant relative market share in through an aggressive pricing strategy. Therefore, an immediate action to curb the present surge in imports from the exporting country would be in the interest of domestic industry.
- k. Most of the companies suffered lower capacity utilization due to pressure from increased imports coupled with drastic fall in profits and a meagre return on capital employed.
- l. A comprehensive evaluation of parameters such as production capacity, production, capacity utilization, employment, productivity, cash flow, return on capital employed, captive use, stocks, consumption, sales, market share, price, and profitability of the period from 2004 up to the end of the financial Year 2007-2008 will demonstrate serious injury or significant impairment of the Indian producers of LAB. It is further submitted that there is a direct correlation between the increase in imports at lower prices and serious injury suffered by the domestic industry and the increase in imports has had injurious effects in terms of pressure on prices and a reduction in volume sold by the domestic industry.
- m. Imposition of safeguard duties of at least 20% for a period of one year from the date of imposition followed by 15% in the second year and 10% in the third year has been requested. The levels of duties requested shall allow the domestic industry to reduce its costs with the several measures it has already undertaken or proposes to undertake in the corresponding time. There is an immediate need to protect the domestic industry by way of provisional duties to enable them improve their profitability and ROCE.
- n. The constituent elements of the domestic industry have taken measures to fully utilize the capacities by a series of decisions including (i) de-bottlenecking, (ii) ensuring feedstock supply for such de-bottlenecked capacities, etc. The increases in capacities pursuant to the above steps are likely to result in optimization of operating costs. Since these are de-bottlenecking operations, there would be little increase in the Fixed Costs.

Each member of the domestic industry is following different approaches to restructuring. The domestic industry is preparing for shifting from liquid fuel to natural gas for this purpose. At the completion of this switch over process, it is estimated that saving in energy cost could increase the competitiveness of LAB manufacture.

**II. Views of the interested parties:** In their submissions dated 16.01.2009, M/s Hindustan Unilever Ltd brought out the following points:

- a. Petitioners have not provided a non-confidential summary of the information claimed to be confidential. This seriously impairs the right of the interested parties to make meaningful submissions.
- b. 'Public interest' considerations play an important role in the administration of trade remedial measures such as safeguard duties and quoted the case of United Phosphorous vs Director General safeguard, 2000 (118) ELT 326 (Del).
- c. LAB is an intermediary product and is an important input in the manufacture of detergent bars and powder and constitutes around 50 to 60% percent of the final product cost. Any increase in the prices of the input (LAB) will most certainly increase the costs of final products. The demand for detergents in India is very elastic and in the absence of viable alternatives, the consumers will be forced to purchase them even at increased prices.
- d. The price of LAB has increased and such increase in prices has resulted in a proportionate increase in the prices of detergents and has impacted nearly 20 crore Indian households since detergent powders and bars are consumed in every Indian house. Further, the detergent industry in India comprises of thousands of tiny units, small scale industries and a few medium and large scale manufacturers. The detergent industry is highly labour intensive as compared to the LAB industry. It employs over five lakh workers, which is significantly high as compared to the LAB industry which employs only around 500 workers. In the event that safeguard duties are levied on imports of LAB into India, it may adversely affect the viability of the downstream detergents industry and thereby affect the very livelihood of the lakhs of workers employed in this industry.
- e. The four constituents of the domestic industry are multi-product, large manufacturing companies. Manufacture and production of LAB constitutes only a small percentage of the overall business of these companies. Given the large size of the Petitioners and the relatively small presence of LAB in their product portfolio, it is unlikely that they may suffer 'significant overall impairment' due to increase in imports of LAB alone.
- f. The total production of LAB by the domestic industry has increased but parallel to the decrease in the share of the domestic industry in total domestic consumption there has been a corresponding increase in domestic industry's export production. This implies that there has been a

significant shift in the sales pattern of the domestic industry which is veering more towards exports. The share of exports in the total installed production capacity is significantly high, which goes on to show that LAB produced in India is increasingly being diverted to the export market. The loss in domestic market share by the domestic industry if any, is self inflicted and does not show any degree of injury to the domestic industry.

- g. Petitioners have been operating at significantly high level of capacity utilization.
- h. It has been a consistent practice with the Hon'ble Designated Authority to determine the existence or threat of serious injury to the domestic industry on the basis of the most recent data on imports.
- i. The Petitioners have failed to establish the existence of a causal link between increased imports of LAB and the alleged serious injury being suffered by them.
- j. The claims by the Petitioners on their plants being shut down are misleading. Both Tamilnadu Petroproducts Ltd. as well as Reliance Industries Limited are large petro-chemical manufacturers and the information on plant shut downs relates to temporary shut downs possibly for general maintenance and up-gradation purposes or unavailability of feedstock. Contrary to the claims made by the Petitioners, their plants were shut not because of the increase in imports of LAB into India and their inability to sell LAB, but for temporary reasons such as maintenance for general wear and tear. Instead the Petitioners continue to produce and sell LAB both in the domestic market and the export market.
- k. The consumers of LAB have been facing several constraints in procuring LAB from domestic sources. This forced the users of LAB to make alternate arrangements and explore the option of meeting their demand through imports. The difficulty in procuring LAB domestically has been further aggravated by the increasing trend amongst the domestic producers to substitute domestic sales by exports.
- l. A review of the details provided by the domestic industry in its petition shows that their efforts to adjust to the increased imports are grossly inadequate and further highlights the incongruity of their claims that they are suffering injury due to increased imports.
- m. In light of the above, there exists no serious injury or threat of serious injury to the domestic industry for LAB due to increased imports of LAB into India.

III. M/s Fena (P) Ltd, New Delhi, Advance Surfactants India Ltd, New Delhi, A.R.Stanchem Pvt.Ltd, Kolkata, New India Detergents Ltd, New Delhi, Rohit Surfactants (P) Ltd, Kanpur, Sai Sulphonates Pvt Ltd, Kolkata, Shantinath Detergents (P) Ltd, Kolkata, Small Scale Detergents & Soap manufacturers Association, Kolkata and Standard Surfactants Ltd, Kanpur filed submissions before Director General Safeguards through their authorized representative on 14.1.2009. The main arguments put forth are:

- a. Import statistics is outdated and may not represent the current state of affairs. The investigation was initiated in December 2008. However, the petition presents import statistics only upto Financial Year 2007-08. Normally, when the investigation is initiated, import statistics as close to the date of initiation as possible shall be given. The domestic producers may be asked to provide a revised and updated petition giving information relating to imports as well as their own production costs, sales revenues, etc for the completed three quarters of the current year 2008-09.
- b. The plants of domestic producers are running and hence the claim of closure of plants is false.
- c. There is no fall in production.
- d. The end-users of LAB are medium and small sized enterprises as compared to the large industrial groups that manufacture LAB. The LAB producers have been acting as a cartel and are maintaining their domestic prices at artificially higher levels. Domestic selling prices charged by all the four domestic producers have always been in tandem. Domestic selling prices have been significantly higher than the prices at which they export to other countries; Import prices are somewhere in between their domestic prices and export prices.
- e. Indian end users of LAB have been paying very high prices charged by the domestic producers of LAB and the present petition seeking imposition of safeguards duty is only to preserve superlative profits.
- f. LAB is already subject to basic customs duty at the rate of 7.5%. On the finished consumer detergent products, there is a peak import duty of 10%. Therefore, imposition of safeguards duty on LAB will lead to an inverse duty structure where the custom duty on a basic raw material will be higher than the duty applicable on the finished products.
- g. Any increase in the cost of LAB will directly affect the prices of detergents and will eventually lead to lower production and sale of detergents. As against 4 manufacturers of LAB, there are over 4000 manufacturers of detergents in India. They employ over 500,000 persons as against 500 persons employed by LAB producers. Thus, levy of safeguard duty will jeopardize the employment opportunities of a large number of employees than non-levy of safeguard duty.
- h. 'Critical Circumstances' do not exist in the present case warranting imposition of provisional safeguard measures.
- i. It has further been contended that it is important and mandatory to consider 'all relevant factors' under Art. 4.2(a) to arrive at Serious Injury.
- j. Further import prices of LAB are mostly higher than export price of Indian LAB manufacturers. It may be observed that at least 30% of the total domestic production is being exported by the domestic industry. It is unrealistic to assume that if the domestic industry is suffering a loss in domestic market, they will export such high quantities at lower prices.
- k. As per the market intelligence available with the importers, the average net sales realization and margin of domestic industry range between -5% to 23%.

- l. No case of critical circumstances has been made out.
- m. They have also contended that the imposition of provisional or final measures would be against 'public Interest' and Article 3.1 of the AoS obligates the investigating authorities to hold public hearings or provide other appropriate means for interested parties (importer, exporters, producers, etc.) to present their views.
- n. Further, the Initiation Notice dated 19th December 2008 does not contain any reference to unforeseen developments that had occurred as a result of obligations undertaken by India before WTO.
- o. Capacity addition in the four exporting countries from Middle East is just 15,000 Tons or a meagre 4.6% and therefore, does not present a threat of material injury to domestic industry in absence of which preliminary safeguards duty should not be levied. Such insignificant capacity additions are common in business and at best, the above changes can be termed as "developments" but can never be termed as "unforeseen developments as a result of obligations undertaken by India".
- p. As submitted above (and admitted by Domestic Industry) the comparative advantage in raw material is reflected in the prices and volumes for which no safeguard duty can be imposed. The oil production in Middle East is a widely known factor since several decades. The objective of trade remedy measures including safeguards is not to allow companies to earn 'super normal profits' by seeking protection from their national governments.
- q. It has been contended that no credible Restructuring plan has been presented by the domestic Industry.

IV. The representatives of M/s Fena (P) Ltd, New Delhi, Advance Surfactants India Ltd, New Delhi, A.R. Stanchem Pvt. Ltd, Kolkata, New India Detergents Ltd, New Delhi, Rohit Surfactants (P) Ltd, Kanpur, Sai Sulphonates Pvt Ltd, Kolkata, Shantinath Detergents (P) Ltd, Kolkata, Small Scale Detergents & Soap manufacturers Association, Kolkata and Standard Surfactants Ltd, Kanpur filed additional submission on 23.01.2009. The main submissions are as follows:

- a. It has been contended that 'Critical Circumstances' do not exist in the present case warranting imposition of provisional safeguard measures. In supports of their contention, they have referred Argentina-Footwear case in WTO, Textile Monitoring Body (TMB) meeting held in January, 2000 and Agreement on Safeguard to emphasize the need of existence of Critical Circumstances. It has further been contended that it is important and mandatory to consider 'all relevant factors' under Art. 4.2(a) to arrive at Serious Injury. In support of the contention, they have referred the US-Wheat Gluten case in the Appellate Body and Panel Report on Korea – Dairy case.
- b. Regarding their contention of absence of serious injury and absence of critical circumstances warranting imposition of provisional duty, they have contested that the outdated data is not relevant to determine the critical circumstances. It is undisputed that cost of production of LAB is completely based on crude prices, but the domestic prices do not reflect the falling crude prices.

- c. Further import prices of LAB are mostly higher than export price of Indian LAB manufacturers. It may be observed that atleast 30% of the total domestic production is being exported by the domestic industry. It is unrealistic to assume that if the domestic industry is suffering a loss in domestic market, they will export such high quantities at lower prices.
- d. As per the market intelligence available with the importers, the average net sales realization and margin of domestic industry has varied from -5% to 55%.
- e. In domestic industry admits that employment may not indicate the real pressure on domestic industry. On the other hand levy of provisional measures directly affects the detergent industry comprising of thousand of tiny units, KVIC units, Small Scale Industries and few Medium and Large Manufacturers. It employs over five lacs workers and caters to the daily hygiene needs of washing clothes of over 120 crores population comprising of 200 million households in India.
- f. They have also contended that the imposition of provisional or final measures would be against 'public Interest' and Article 3.1 of the AoS obligates the investigating authorities to hold public hearings or provide other appropriate means for interested parties (importer, exporters, producers, etc.) to present their views and to respond to the views of others with respect to the matters being investigated. One such issue on which parties' views are required to be sought is whether or not a safeguard measure would be in the public interest.
- g. In the present case, detergent industry comprises of thousand of tiny units, KVIC units, Small Scale Industries and few Medium and Large Manufacturers and employs over five lakh workers whereas the LAB industry consists of four large industrial units and employs merely 500 workers. Further, LAB alone constitutes over 50 to 60% of the raw material cost of detergent products. Some LAB is also used in the manufacture of other products like Pesticides and Emulsifiers used in agriculture by poor farmers and other chemicals like textile auxiliaries used in textile industry etc. On the other hand out of the four domestic manufacturers of LAB two are Fortune 500 Companies for whom LAB business is very insignificant i.e. less than 1% of their total business. Therefore, it is submitted that the imposition of provisional/final safeguard measure in the present case would be against public interest and violative of Article 3.1 of AoS.
- h. The domestic industry contends that Initiation is in violation of Article XIX of GATT 1994 as no unforeseen developments appear to have occurred Further, in terms Article XIX of GATT 1994, a safeguard measure can only be imposed when there is a sudden surge in imports as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under GATT, which causes or threatens to cause serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of that contracting party..
- i. The capacity addition in the four exporting countries from Middle East i.e Iran, Qatar, Saudi Arabia & UAE is just 15,000 Tons or 4.6% .



- j. Further, the petition itself acknowledges that Indian manufacturers are saddled with high energy and power costs unlike in the Middle East. It may be noted that this is the comparative advantage enjoyed by Middle East for global trade because of ample availability of raw material. Also, this comparative advantage will be enjoyed for years to come and was foreseeable at the time of Uruguay Round Negotiations. Imposing safeguards duty against the comparative advantage will amount to penalizing an exporter for the natural resources it possesses which goes against the basic tenets of WTO Agreement in general & AoS in particular.
- k. It is contended that the Parameters mentioned in the petition do not support 'serious injury' or 'threat of serious injury' as:
- The capacity utilization reached to the level of 95% in POI
  - Inventories have declined in the period of investigation as compared to previous year as well as base year.
  - There is no fall in the production quantities during 2007-08. On the contrary, production has increased from 4.65 lac MT during 2006-07 to 4.71 lac MT during 2007-08.
  - It is contended that The Parameters mentioned in the petition do not support 'serious injury' or 'threat of serious injury'.
- l. As submitted above the comparative advantage in raw material is reflected in the prices and volumes for which no safeguard duty can be imposed. The oil production in Middle East is a widely known factor since several decades. The objective of trade remedy measures including safeguards is to facilitate structural adjustment that would enhance rather than limit international competition. It has been contended that no credible Restructuring plan has been presented by the domestic Industry. Thus the measures may not be imposed unless they are limited to the extent necessary to prevent or remedy serious injury; and they facilitate adjustment.
- m. Further there appears to be no co-relation between the proposed reduction in cost and the level of duties in force or the level of duties sought by them.

V. Further submissions by Domestic Industry: The applicants filed additional submissions on January 22, 2009. The main points put forth by them are:

- a. In response to M/s Hindustan Unilever Ltd., the domestic industry submitted that it has given all the non-confidential data regarding serious injury in the non-confidential version of the application submitted. It was submitted that they have provided all the indexed figures on the various injury factors which clearly show the trend of the various individual injury factors such as production, sales, capacity utilization, profitability, return on investment etc. The data regarding costs, profitability, ROI etc are highly business sensitive information, the disclosure of which would be of significant competitive advantage to the competitors and would adversely affect their business. The domestic industry, has, therefore claimed

confidentiality in terms of Rule 7(1) of the Safeguard Rules and the indexed figures have been provided.

- b. As regards the reference to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the Reliance case, it is submitted that the same is not at all relevant and has been quoted completely out of context. In that case, the Designated Authority had claimed confidentiality and it was held by the Hon'ble Supreme Court that the right to claim confidentiality in terms of the provisions of Rule 7 of the Anti-dumping Rules is not available to the Designated Authority. Therefore, the said judgment is of no relevance.
- c. The detailed restructuring plans of the domestic industry have indeed been attached to the confidential version of the application. Since these plans are company-specific and contain commercially sensitive information, the Domestic Industry had sought protection under Rule 7(1) of the Safeguard Rules. Therefore, the details of the restructuring plans cannot possibly be shared with the other interested parties.
- d. As regards Public Interest, it has been submitted the argument advanced by HUL is without any merit whatsoever as the safeguard laws are meant to protect the legitimate interests of the Domestic Industry of the country from increased imports. If the argument of HUL is accepted, it would render the entire safeguard law meaningless as the purpose and object sought to be achieved by safeguard duties is to protect the Domestic Industry against increased imports. Further, imposition of safeguard duty does not encourage monopolistic practices but protects the interests of the domestic producers, if increased imports cause or threaten to cause serious injury to them so as to allow them sufficient time to meet the competition offered by increased imports.
- e. The scope of the term "Public Interest" is not restricted to cover consumer interest alone. "Public Interest" is a much wider term covering in its ambit the general social welfare of the larger community interest which includes the interest of the manufacturers as well. While the imposition of safeguard duty may result in the increased cost of imported LAB into India, it is important to keep the prime objective of safeguard laws in mind. The purpose of its imposition is to provide sufficient time to the domestic industry to make positive adjustments to meet the situation of increased imports. The imposition of safeguard duty would allow the users/buyers a wider choice to source their material requirements, that too at a competitive price.
- f. HUL has relied upon the decision of the Hon'ble Delhi High Court in the case of United Phosphorus Vs. Director General (Safeguards) in support of its arguments for public interest. Without prejudice to our contention

that public interest in the context of safeguard laws would be served if the domestic manufacturers are protected against increased imports, it is submitted that the said decision has been cited wholly out of context. In that case, the DG decided that since the Domestic Industry had stopped production, it would be difficult to appreciate that even after three years indigenous product can be made available to the domestic users/consumers at competitive prices. The DG had therefore reached a conclusion of not recommending safeguard duties after considering such relevant factors as the likelihood of the success of the restructuring plan. Thus, it is apparent that the decision of the DG was based on the inability of the Domestic Industry to improve over a period of time. The decision of the Hon'ble Delhi High Court was in this context only wherein it was held that the DG has to consider other aspects as well under the Rules. There is not even a whisper that the decision of the Hon'ble Delhi High Court empowered the DG to look into the aspects of public interest at large so as to include the interests of the user industry as well. It is therefore reiterated that the public interest, as envisaged under the Safeguard Rules and elaborated by the Hon'ble Delhi High Court, will be met with if the state of the domestic producers of the product under consideration is examined on the basis of the parameters provided under the Rules.

- g. HUL and the importers/end-users may be asked to give detailed information as to how the employment situation in the detergent industry was impacted when the prices of LAB had gone up due to the overall increase in the crude prices. It would become apparent that HUL and the importers merely are raising the bogey of employment and larger public interest to protect their profit margins at the cost of the beleaguered LAB industry.
- h. The domestic industry also provides employment to a number of people in the country, thereby making a valuable contribution to the economy of India. Imposition of safeguard duty will only allow the domestic producers to survive the new face of competition through increased imports, which will benefit the buyers of LAB as well as the final end users/consumers in the long run.
- i. HUL has argued that there is a lack of serious injury to the domestic industry. This argument is again baseless, as the domestic industry has given ample evidence of serious injury caused by increased imports of LAB.
- j. Serious Injury: HUL has claimed that there is no serious injury to the domestic industry on account of increased imports of LAB. In this context,

it may be relevant to quote the provisions of Clause 6 (c) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, which defines "Serious Injury to mean an injury causing significant overall impairment in the position of domestic industry". Further in determining whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Annex to the Safeguard Duty Rules requires the Director General to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses and employment.

- k. An analysis of the various parameters clearly indicates that the domestic industry has suffered serious injury due to increased imports. The imports have increased in absolute terms as well as relative to the apparent consumption in the country indicating that a major slice of the domestic market share has been taken over by cheap imports.
- l. It may be observed from the data submitted by the domestic industry that the domestic industry is suffering serious injury on all the major economic and financial parameters. It may be seen from the submissions made by the domestic industry that the market share of the domestic industry has fallen drastically in 2007-08 as compared to the year 2005-06. Most of the companies suffered lower capacity utilization due to pressure from increased imports coupled with a situation of losses from erstwhile profits and a meager return on capital employed. There is a direct correlation between the increase in imports at lower prices and serious injury suffered by the domestic industry. The increase in imports has had injurious effects in terms of pressure on prices and a reduction in volume sold by the domestic industry.
- m. As regards the high Capacity Utilization by the Domestic Industry, it is submitted the capacity utilization of the Domestic Industry has seen a fall over the injury investigation period. But for the increased imports, the Domestic Industry would have been able to cater to the additional demand without any difficulty keeping in view its achievable capacity.
- n. HUL has stated that since LAB constitutes only a small percentage of the overall business of the petitioners, it is unlikely that they may suffer significant overall impairment due to increase in the imports of LAB alone. It may be appreciated that safeguard duty is product specific. The injury suffered by the domestic industry due to increased imports is for the product concerned i.e., LAB and not for the other products. Most of the

petitioner companies are multi-product companies. It is important to note that the injury analysis is done for the specific product under question and not for the whole company when such separate identification of that product based on production process, producers, sales and profits is possible. This position has also been affirmed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Reliance Industries Ltd. Vs. Designated Authority [2006 (202) ELT 23 (SC)]. The same ratio has to apply for safeguard duties as well. It is very clear from the submissions made by the domestic industry that they are suffering serious injury in LAB due to increased imports of LAB and the reference to their other operations is legally and logically of no consequence.

- o. HUL has claimed that the domestic sales are being substituted by exports. In this connection, it is submitted that a significant decline in ROI and a situation of loss coupled with significant price undercutting and underselling despite suppressed domestic prices caused by the cheap and increased imports have forced the domestic industry to increase its share in the export markets. If the Domestic Industry decides not to export, it would directly affect their total production thereby increasing the overall costs and losses. In fact, if the Domestic Industry is able to increase its sales to the domestic market, it would certainly like to do so as the realization in the domestic market is better. In fact, the whole objective of this application is to increase the market share in the domestic market. The argument of HUL is therefore devoid of any merit.
- p. As regards the claim that the cause of injury to the domestic industry is not increased imports as these imports were necessitated to meet the gap between domestic supply and domestic demand, it is submitted that it would be more profitable for the Domestic Industry to sell in the domestic market as compared to exports but it is precisely because of the increased imports that the Domestic Industry is unable to sell in the domestic market. Further the domestic industry has only requested for imposition of safeguard duty on imports of LAB in accordance with the law so as to enable them to adjust to the situation of increased imports.
- q. HUL has also argued that the injury to the domestic industry is self-inflicted and due to intrinsic inefficiency and insufficient restructuring plans. The domestic industry has already identified the various restructuring and adjustment plans so as to meet the increased competition from imports. The desirability and need for imposition of safeguard duty needs to be assessed and determined in the context of whether there is a reasonable possibility of the domestic industry making positive adjustments and becoming competitive. The domestic industry, in the

present case, has already identified its adjustment plans and have requested for imposition of safeguard duty so as to enable them to take necessary steps to protect them from the serious injury caused by increased imports. Besides, the domestic industry is well aware of the fact that safeguard measures are of temporary and short-term nature provided only to protect the domestic producers to make readjustments and face the competition from increased imports.

VI. In response to submissions of M/s Fena (P) Ltd, New Delhi, Advance Surfactants India Ltd, New Delhi, A.R. Stanchem Pvt. Ltd, Kolkata, New India Detergents Ltd, New Delhi, Rohit Surfactants (P) Ltd, Kanpur, Sai Sulphonates Pvt Ltd, Kolkata, Shantinath Detergents (P) Ltd, Kolkata, Small Scale Detergents & Soap manufacturers Association, Kolkata and Standard Surfactants Ltd, Kanpur the applicants stated as follows:

- a. These importers have not filed the importer's questionnaire before the DG. Therefore, it would be appropriate if the present submissions of the importers are ignored as the Domestic Industry cannot be called upon to comment upon the submissions in a piecemeal manner. This approach certainly impedes the investigation process and acts prejudicial to the interests of the Domestic Industry.
- b. As regards the alleged outdated Import Statistics, it has been stated that the argument though theoretically attractive has no legal or logical support.
- c. There is no legal provision which suggests that the period immediately preceding the initiation must be taken into account by the DG. On the contrary, in the case US Line Pipe case (following Appellate Body decision in the Argentina Footwear (EC) case), the WTO Panel held that "the word 'recent' implies some form of retrospective analysis. It does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the Authority's decision."
- d. If the POI is constantly revised after initiation, it would lead to a situation where the investigation would become a never-ending exercise.
- e. The importers have not indicated as to how the circumstances have significantly changed after the proposed POI. A mere statement that the prices have changed is not sufficient to question the POI taken for the purpose of enquiry. This is without prejudice to our contention that the DG can take into account only the information relating to the POI except for examining the issue of critical circumstances for the purpose of provisional duties.
- f. The Domestic Industry had filed the application as early as in July 2008 with the most recent data reasonably available to the domestic Industry and hence the submission is without any substance.
- g. The apprehension regarding a high NIP (due to the proposed POI) is ill-founded as the comparison for the purpose of price underselling is always

made with the imports of the corresponding period. It is therefore clear that the importers are merely attempting to delay or block the imposition of provisional duties by raising frivolous issues.

- h. The Designated Authority in the Ministry of Commerce has recently initiated several investigations where the import data is more than nine months old. In this context, the decision of the Hon'ble Rajasthan High Court in the case of RTMA Vs. Designated Authority [2002 (149) ELT 45 (Raj.)] may be referred to. Though that decision is rendered in the context of anti-dumping investigations, the ratio is squarely applicable to the safeguards investigations also as the relevant provisions are identical.
- i. If the contention of the importers is accepted that the Domestic Industry should give the information for the three quarters of the financial year 2008-2009, it would amount to a diktat by the importers as to how the POI should be determined without any legal, factual or logical support.
- j. Any revision of the POI, which is legally not necessitated, would be detrimental to the interests of the Domestic Industry which is already suffering on account of increased imports.
- k. An analysis of the various parameters clearly indicates that the domestic industry has suffered serious injury due to increased imports. The imports have increased in absolute terms as well as relative to the apparent consumption in the country indicating that a major slice of the domestic market share has been taken over by cheap imports.
- l. It may be seen from the submissions made by the domestic industry that the market share of the domestic industry has fallen drastically in 2007-08 as compared to the year 2005-06. Most of the companies suffered lower capacity utilization due to pressure from increased imports coupled with a situation of losses from erstwhile profits and an inadequate return on capital employed. There is a direct correlation between the increase in imports at lower prices and serious injury suffered by the domestic industry. The increase in imports has had injurious effects in terms of pressure on prices and a reduction in volume sold by the domestic industry.

## 11. Findings of the DG:

I have carefully gone through the case records and the replies filed by the interested parties and the domestic producers. Submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the finding below:

### I. Issuance of Preliminary Findings and Observance of Natural Justice:

The issue to impose immediate safeguard measures was examined. It has been found that a total of 168 Safeguard Initiations have been reported to the WTO during the period between 29.03.1995 and 12.11.2008. It has been observed that in 15 of these cases provisional safeguard measures have been recommended/imposed within 30 days of initiation of the safeguard investigation. In some cases the provisional safeguard measures have been recommended on the same day as the date of initiation of the



investigation. The Rule 9 of Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 notified vide Notification No. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997 prescribes that the Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury. The principles governing investigations have been provided in the Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, which is independent to Rule 9. The Rule 15 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules provide for refund of differential Safeguard duty in case safeguard duty imposed after conclusions of the investigations is lower than the provisional duty already imposed and collected. The harmonious reading of Rules 6, 9 and 15 of the said Rules leads to a conclusion that the Rules provide for expeditious recommendation of provisional Safeguard duty based on preliminary findings and refund of the differential duty in case it is ascertained that the duty imposed after conclusion of investigation following natural justice as enshrined in the Rule 6 is lower than the provisional Safeguard Duty. However, in critical circumstances any delay in imposition of Provisional Safeguard duty may cause damage which would be difficult to repair. Accordingly, it is my considered view that the issuance of preliminary findings and imposition of provisional duty is in complete conformity with the tenets of Natural Justice.

## **II. Confidentiality of Certain Information:**

The representatives of HUL contended that undue and excessive confidentiality claimed by the Petitioners seriously impaired the right of the interested parties to make meaningful submissions. They also requested that the Designated Authority to direct the Petitioners to disclose all pertinent information especially all details of restructuring plans to the interested parties, including the Importer. I went through the restructuring plan submitted by the applicant as confidential documents, and I found that the restructuring plan is detailed, specific and based on technical and economic parameters. It is the restructuring plan which is supposed to make the Industry competitive enough to face competition from imports once the term of safeguard measures are over. A restructuring plan is intended to bring efficiency and it is the relative efficiency which brings competitiveness. A restructuring plan is an intellectual property and the secrecy of the plan helps managing change on account of restructuring. Further, the confidentiality helps maintain a lead over competitors.

However, I also appreciate a need of disclosure of certain information for effective rebuttal by the other interested parties and also to maintain transparency in decision making. In order to maintain harmonious balance between the two competing interests, I have disclosed in the preliminary findings all relevant information except those which have been claimed to be confidential and at the same time I am of the view that disclosure of which would seriously injure interest of the party claiming confidentiality.

- III. Product:** The product under investigation is "All Linear Alkyl Benzene, Mixed Alkyl Benzene. It falls under sub-heading No. 38170011 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975, sub-heading No. 38170011 of ITC and sub-heading No. 38170011 of HSN. The subject matter of investigation is only Mixed Alkyl Benzenes and Linear Alkyl

Benzenes and not Mixed Alkyl Naphthalenes. The above product is generally known as 'Linear Alkyl Benzene' (for short "LAB") in commercial market parlance.

The domestic industries use Kerosene, (Extracted - C10-C13 Paraffins) and Benzene as raw materials for the production of Linear Alkyl Benzene. C10-C13 Paraffins are extracted from the Hydrobon Molex Process, from Feedstock Kerosene. These Paraffins are converted to their Olefins, by selective dehydrogenation, at high temperature. The C10-C13 Olefins are then alkylated to Benzene, to form Linear Alkyl Benzene. The linear alkylbenzenes produced from C10C13 linear olefins are useful detergent intermediates and can be readily sulfonated to yield linear alkylbenzene sulfonates. These compounds constitute the "active" ingredients of household detergents. They are surface active compounds (surfactants) which are combined with various builders (often inorganic salts) to make up a detergent. In short, LAB is used as an important input by the detergent industries.

IV. **Domestic Industry:** The present investigation arises on an application made by M/s. Reliance Industries Ltd., Mumbai, Tamilnadu Petroproducts Ltd., Chennai, Nirma Ltd., Ahmedabad and supported by Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi. The shares of these companies are as mentioned below:

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Company	Share	Share	Share	Share
Indian Oil	11%	24%	26%	28%
Nirma	26%	21%	19%	19%
Reliance	40%	38%	36%	37%
TPL	23%	18%	19%	17%
Total	100%	100%	100%	100%

The share of the applicants excluding Indian Oil, who is supporting, is 72% during 2007-08 and 100% when Indian Oil is also considered with the applicants. Accordingly, the applicants constitute domestic industry in terms of clause (b) of subsection (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

#### V. Unforeseen Developments:

a) The Article XIX of GATT 1994 which reads as:

" 1. (a) If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement,....." uses the term 'unforeseen developments'. The use of

plural term, 'developments' implies that there could be more than one development whose combined effect may be considered. Further, in practice all developments may not be independent and in fact such developments may influence each other. It is the effect of resonance of all such developments which impact the business dynamics and tilt the odds from one to another. Therefore, in order to consider unforeseen developments and the result thereof, it is necessary to take holistic view.

- b) Preliminary investigations indicate that the majority of LAB imports are coming from Middle East (Qatar, Iran and Saudi Arabia) where additional capacities have come up. Around 70% of the capacities in these countries are used for export market. It is observed that India has shown robust growth in 2007-08 and the same is continuing in 2008-09. The strength of growth can be deduced from the fact that even when many developed countries have declared the arrival of recession, India is continuing with the growth. The stagnation in demand of developed countries having large per capita consumption, naturally, makes the trade look towards the area where there is a demand and growth of demand. The combined effect of change in outlook of trade, changes in world order coupled with other developments like creation of extra capacities abroad are the developments, which was difficult to be foreseen and has led to increased imports and consequent injury.

#### VI. Increased Imports:

- It is apparent from the Table below that there has been increase in import volume in 2007-08 over the period 2006-07. Further, the imports in 2006-07 were significantly higher than 2005-06. This increasing trend continues up to September 2008.
- The relative increase in imports compared to domestic production as well as domestic sales have been studied and found that there has been significant increase in share of imports compared to domestic production from 7.25% in the year 2006-07 to 14.27% in the year 2007-08. The similar trend continues in the later months. The share of imports in total sales in India has gone up from 7.22% to 13.91% in 2007-08, with continuing trend in later months, as given in the following tables.

Imports of LAB in India			
	Quantity (MT)	Value (Rs. in lacs)	Price (Rs. PMT)
2004-05	9854	3913	39710
2005-06	4871	2314	47506
2006-07	21470	11491	53521
2007-08	45505	25474	55981

April 2007-Sep 2008 (18 Months)	70806	47682	67586
April 2007-Sep 2008 (Annld)	47004	31768	67586

Increasing Import Vis-a-Vis Domestic Industry					
	2005-06	2006-07	2007-08	Apr07-Sep08 (18 Months)	Apr07-Sep08 (Annld)
Share of imports vis-a-vis domestic production	1.69%	7.25%	14.27%	14.55%	14.55%
Share of domestic production (total)	98.31%	92.75%	85.73%	85.45%	85.45%
Market share of Imports vis-a-vis total domestic sales	1.73%	7.22%	13.91%	14.40%	14.40%
Share of domestic sales	98.27%	92.78%	86.09%	85.60%	85.60%

Further, the comparison of cost of sale taking reasonable ROCE and the import prices, it is observed that the imports are at lower prices. Accordingly, I find that there is increase in imports in absolute as well as relative term and the increase in imports during recent period is significant.

**VII. Serious Injury:** In order to determine whether there is serious injury to the domestic industry, I have examined the various factors including those envisaged under paragraph 1 of Annex to the Safeguard Rules in the following paragraphs:

**a) Sales and Market Share of domestic industry:** The sales volume of the domestic industry has gone down during the period under consideration as

compared to the immediately preceding year. The market share of the total domestic industry (including IOCL) has fallen from 98% in the base year to about 86% in the POI, a fall of about 12%. It is also important to note that the market has shown a growth of over 16% during the period 2007-08. sales volume of the domestic industry fell by 9083 MT during April 07 to September 2008 (Annualized) as compared to 2005-2006 i.e., a fall of about 5%. Further, the sales volume of the Domestic Industry has come down despite the fact that the total demand and the size of the Indian market has gone up by as much as 45569 MT, an increase of about 16%.

	2005-06	2006-07	2007-08	Apr07-Sep08 (18 Months)	Apr07-Sep08 (Annlzd)
<b>Imports</b>	4871	21470	45505	70506	47004
<b>Share of imports vis-à-vis domestic production</b>	1.69%	7.25%	14.27%	14.55%	14.55%
<b>Share of domestic production (total)</b>	98.31%	92.75%	85.73%	85.45%	85.45%
<b>Market share of Imports vis-à-vis total domestic sales</b>	1.73%	7.22%	13.91%	14.40%	14.40%
<b>Share of domestic sales</b>	98.27%	92.78%	86.09%	85.60%	85.60%

b). **Capacity Utilization & Production:** While the production of the domestic industry has declined during the period 2007-08 as compared to the year 2005-06, there is an increase of a negligible (0.027%) as compared to the immediately preceding year. It is important to note that the capacity utilization has fallen from 104% in the base year to 96% during the period April 2007- September 2008. This is despite the fact that the market size has increased by about 16%. It is therefore clear that the domestic producers have not been able to take a fair share of the growing market.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	Apr07-Sep08 (18 Months)	Apr07-Sep08 (Annld)
Installed capacity	MT	448500	448500	497338	746007	497338
Actual Production	MT	467765	459192	470331	716613	477742
Capacity Utilization	%	104%	102%	95%	96%	96%

c). **Productivity:** There is no indication to suggest that the injury is on account of loss of productivity.

d). **Profitability:** The profitability of the domestic industry has declined substantially during the period of 2007-08 as compared 2005-2006. As compared to the profit of the Domestic Industry of Rs. 100 (Indexed) in 2005-2006, there is a loss of Rs. 41 (Indexed) in 2007-08. There is a loss of Rs. 42 (Indexed) per MT in the 2007-08 against a profit of Rs. 100 (Indexed) per MT in 2005-2006.

e). **Employment:** There has been no significant impact on employment. The reason being all the Indian producers are multi-product companies and the existing labour laws. However, the Domestic Industry submits that if the present situation does not improve, the adverse impact on employment is imminent.

f). **Price Analysis:** An analysis of the landed value and the current net sales realization clearly shows the existence of price undercutting to the extent of about 6%. It is also observed that the domestic industry is suffering on account of price underselling..

A comprehensive evaluation of all relevant parameters indicates that there is overall impairment of the domestic industry of LAB. It has been argued by some of the interested parties that the applicants are making profits as per their annual reports. In this connection, it is important to note that the Safeguard Rules requires an assessment of various injury parameters in the context of the product under consideration and not for the company as a whole. Therefore, there is no merit in the argument advanced in this respect.

VIII. **Causal Link:** A comprehensive evaluation of parameters as above for the period from 2004-05 up to the end of the financial year 2007-2008 demonstrates serious injury or significant impairment of the Indian producers of LAB. The market share of the domestic industry has substantially declined during 2007-08, as discussed above. During the same period there has been substantial increase in imports both in absolute as well as relative term, due to the commissioning of export-oriented capacities in various countries and the growing Indian market. The declining profitability during the

period 2006-07 and 2007-08 compared to the period 2005-06 coincide with the same period when import increased. The fall in capacity utilization is also found to be there when import increased. This clearly depicts a direct correlation between the increase in imports at lower prices and serious injury suffered by the domestic industry and the increase in imports has had injurious effects in terms of pressure on prices and a reduction in volume sold by the domestic industry.

- IX. Adjustment Plan:** The domestic producers have submitted a detailed adjustment plan with estimated impact on cost. Through these measures constituents of the domestic industries have taken measures to fully utilize the capacities by a series of decisions including (i) de-bottlenecking, (ii) ensuring feedstock supply for such de-bottlenecked capacities, etc. The increases in capacities pursuant to the above steps are likely to result in optimization of operating costs. Since these are de-bottlenecking operations, there would be little increase in the Fixed Costs. Each member of the domestic industry is following different approaches to restructuring. The preliminary analysis of the restructuring plans shows that these are viable restructuring plans.
- X. Other Issues:** It has been contended by the user industries that the detergent industry comprises of thousands of tiny units, KVIC units, Small Scale Industries and few Medium and Large Manufacturers and employs over five lakh workers whereas the LAB industry consists of four large industrial units and employs merely 500 workers. Further, LAB alone constitutes over 50 to 60% of the raw material cost of detergent products. Some LAB is also used in the manufacture of other products like Pesticides and Emulsifiers used in agriculture by poor farmers and other chemicals like textile auxiliaries used in textile industry etc. On the other hand out of the four domestic manufacturers of LAB two are Fortune 500 Companies for whom LAB business is very insignificant i.e. less than 1% of their total business. While the imposition of safeguard duty may result in the increased cost of imported LAB into India, it is important to keep the prime objective of safeguard laws in mind which is to provide sufficient time to the domestic industry to make positive adjustments to meet the situation of increased imports. It is important to note that the imposition of safeguard duty would allow the domestic industry to remain competitive and, at the same time, users/buyers will have a wider choice to source their material requirements, that too at competitive prices.
- XI. Critical Circumstances:** The increasing share of domestic market taken by imports at injurious prices, unutilized production capacity and idling of capacities to minimize inventory losses are the critical circumstances for issue of preliminary findings as the damage caused by delay will be difficult to repair.
- XII. Developing Countries:** The table below contains the percentage of imports from the exporting nations. There have been imports from Iran (24%), Malaysia (4%), Qatar (37%), Saudi Arabia (16%), which are more than 3%. Exports of the product from all other developing countries taken together do not contribute more than 9% of exports to India. Accordingly, imports of LAB from all developing nations as notified vide Notification No. 103/98-Cus dated 14.12.1998 (as amended) except Iran, Malaysia, Qatar and Saudi Arabia, may not attract safeguard duty.



Table

Year 2007-08 Source IBIS				
		Qty (MT)	Value	% share in
			(Rs in Lac)	total imports
				(Volume)
Thailand		14	14	0%
IRAN		10696	5937	24%
Netherlands		1007	527	2%
KOREA RP		14	14	0%
MALAYSIA		1805	1054	4%
QATAR		16661	9676	37%
SAUDI ARAB		7122	3877	16%
U ARAB EMTS		103	51	0%
Switzerland		8083	4325	18%
<b>Total</b>		<b>45505</b>	<b>25474</b>	

## 11 Conclusion and Recommendation:

On the basis of the above preliminary findings it is seen that increased imports of LAB have caused serious injury to domestic producers of LAB. Critical circumstances, where any delay in application for safeguard measures would cause damage which it would be difficult to repair, exist necessitating immediate application of provisional safeguard duty for a period of 200 days, pending a final determination of serious injury and threat of serious injury. Considering the average cost of production of LAB by the domestic producers (confidential), a reasonable return on capital employed, the present level of import duties and the average import prices of LAB, safeguard duty at the rate of 20% ad-valorem, which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, is recommended to be imposed on imports of Linear Alkyl Benzene falling under 38170011 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975.

## 12 Further Process:

- (i) A public hearing will be held in due course before making a final determination, for which the date will be informed separately.

[F. No. D-22011/23/2008]

S. S. RANA, Director General